खबर पेज 7 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

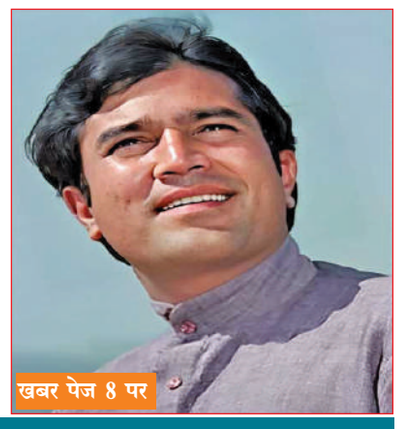

खबर पेज 8 पर

वर्ष -11 | अंक–19 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, मंगलवार 16 – 31 दिसंबर 2025 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

शुभकामना

नए साल के अवसर पर **'गंभीर समाचार'** के सभी पाठकों, विज्ञापनदाताओं व शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 का वर्ष आप सभी के जीवन में नई खुशियां, उपलब्धि व उमंग लेकर आए। हमेशा की तरह आप हमारे साथ बने रहें, यही हमारी कामना है।

संपादक

सुविचार

- अनुमान मन की कल्पना है, और अनुभव जिंदगी का सबक हैं...
- लोग कहते है की तुम संघर्ष करो 'हम तुम्हारे साथ है', यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरुरत ही नहीं पड़ती।

शेरो-शायरी

- अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है छुपाएँ कैसे तेरी मर्ज़ी के मुताबिक़ नज़र आएँ कैसे
- चुपके चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है

इंसाफ के लिए अब 24 घंटे खुलेगी अदालत

सीजेआई सूर्यकांत का ऐतिहासिक फैसला

निज संवाददाता : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की सुनवाई पर बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि लीगल इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत के अनुसार, जांच एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तारी की धमकी दी जाने की स्थिति में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आधी रात को भी सुनवाई की मांग की जा सकती है।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा-मैं प्रयास कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। न्यायालय की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी व्यक्ति लीगल इमरजेंसी में कोर्ट पहुंच सके। मीडिया से बातचीत के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायालयों में भारी संख्या में याचिकाएं लंबित पड़ी हैं, जिनके निपटारे के लिए अधिक से अधिक संवैधानिक पीठ का गठन करने की जरूरत है। इन याचिकाओं में एसआईआर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। बिहार के बाद 11 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत के अनुसार, सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिला को प्रवेश करने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी याचिका दायर हुई है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बीच टकराव का है, जिसके लिए नौ सदस्यीय पीठ बनाने की जरूरत है। सीजेआई सूर्यकांत ने वकीलों के लिए भी नए नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण मामलों में वकील कई दिनों तक बहस जारी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए समयसीमा लागू की जाएगी। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट के वकील तय समय सीमा के भीतर अपनी मौखिक दलीलें रखेंगे। उन्हें समय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा।बता दें कि पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों पर रात को सुनवाई की है। 2005-06 में निठारी कांड, 1992 में अयोध्यास विवाद, 2018 में कर्नाटक सरकार मामला, 1993 में याकूब मेमन फांसी मामले में शीर्ष कोर्ट ने आधी रात को सुनवाई की थी।

अमित शाह ने बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर दिया जोर

भाजपा नेताओं को दिया दो महीने का अल्टीमेटम

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी-अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने तीन दिवसीय बंगाल दौरे के आखिरी दिन यानी बुधवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल में भाजपा की विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को एक एकजुट चेहरा दिखाने और चुनाव में पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया। खास बात यह रही कि पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष को भी इस बैठक में शामिल किया गया, जिन्हें आगामी चुनाव में पार्टी का एक मुख्य चेहरा बनाया जा सकता है। बता दें कि बैठक में भाजपा के सांसद, विधायक, नगरपालिका पार्षद और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। शाह ने दिलीप घोष के अलावा अन्य नेताओं जैसे सुकांत मजूमदार, समिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की, जिससे पुराने और नए नेताओं के बीच तालमेल दिखाने की कोशिश की गई। वहीं इस बैठक के बाद दिलीप घोष ने मीडिया से कहा कि मैं अब सक्रिय रूप से 2026 के चुनाव में नजर आऊंगा। मुझे अपनी राय और अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक जैसे सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देब और अमित मालवीय भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने नेताओं को निर्देश दिया कि वे कम से कम सप्ताह में चार दिन और रोजाना पांच 'स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग' में हिस्सा लें ताकि जनता के बीच पार्टी की पहुंच मजबूत हो। अगले दो महीनों में नेताओं को अपना प्रदर्शन दिखाना होगा, तभी उन्हें चुनावी टिकट मिलने के योग्य माना जाएगा।

राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दीं देशवासियों को शुभकामनाएं

'यह हमारी आस्था का दिव्य उत्सव'

निज संवाददाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपराओं का एक दिव्य उत्सव है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले महीने फहराया गया ''धर्म ध्वज'' पहली बार राम लला की प्रतिमा की स्थापना का साक्षी बन रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या जी की पवित्र भूमि पर राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपराओं का एक दिव्य उत्सव है। इस पवित्र और पावन अवसर पर, देश और विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से, भगवान श्री राम के चरणों में करोड़ों प्रणाम और नमन। सभी देशवासियों को मेरी असीम शुभकामनाएं। मोदी ने आगे कहा कि भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से अनगिनत राम भक्तों का पांच शताब्दी पुराना संकल्प पूर्ण हुआ है। आज राम लला एक बार फिर अपने भव्य निवास में विराजमान हैं, और इस वर्ष अयोध्या का धर्म ध्वज बारहवें दिन राम लला की प्रतिष्ठा का साक्षी है। यह मेरा सौभाग्य है कि पिछले महीने मुझे इस ध्वज की पवित्र स्थापना में भाग लेने का शुभ अवसर मिला।प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कामना की कि सदाचार के प्रतीक राम लला की प्रेरणा प्रत्येक नागरिक के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को गहरा करे, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत नींव बने। इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा द्वादशी और राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की।राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण किया और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

मरीज़ को वेंटिलेशन पर रखने से पहले बताना होगा खर्च का हिसाब

केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस

निज संवाददाताः मरीज़ को वेंटिलेशन पर रखने से पहले परिवार वालों को खर्च का हिसाब बताना होगा। केंद्र की तरफ से यह दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) जारी किया गया है। कहा गया है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर का खर्च एक जैसा होगा। ये दिशा-निर्देश डायरेक्टर जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ ने जारी की हैं। ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ ने प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की हेड एडिशनल डीजीएचएस डॉ. सुजाता चौधरी थीं। सभी मामलों की जांच करने के बाद कमेटी ने नई गाइडलाइंस तैयार कीं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि बुज़ुर्गों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। साथ ही आईसीयू की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में डायरेक्टर जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ वेंटिलेटर के इस्तेमाल में एथिक्स और पारदर्शिता लाना चाहते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि मरीज़ के परिवार को वेंटिलेटर को लेकर कई तरह की शिकायतें रहती हैं। नाराजगी इस बात पर होती है कि अस्पताल के अधिकारियों ने मरीज़ को बिना बताए वेंटिलेशन पर रख दिया। इस प्रक्रिया में इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। अचानक वेंटिलेशन से मरीज़ का परिवार मुश्किल में पड़ जाता है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि मरीज़ के परिवार को साफ़-साफ़ बताया जाना चाहिए कि मरीज़ को वेंटिलेशन की ज़रूरत क्यों है। लिखित मंज़ूरी लेनी चाहिए। मरीज़ के परिवार को इनवेसिव और नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के खर्च के बारे में भी अलग से बताया जाना चाहिए।

नए साल से बदल जाएंगे कई नियम

काम की खबर बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब, सुविधा और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा

निज संवाददाता : नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम भी बदल जाते हैं। इसी क्रम में 2026 की शुरुआत होते ही देश में बैंकिंग, टैक्स, राशन कार्ड, किसानों की योजनाएं, गैस की कीमतें, डिजिटल पेमेंट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और कई दूसरी सुविधाओं से जुड़े नए नियम लागू हो सकते हैं।

इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब, सुविधा और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। किसान हों, नौकरीपेशा लोग हों, बुजुर्ग पेंशनर हों या फिर मिडिल क्लास परिवार, हर किसी के लिए यह जानना जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है, ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सकें।

1. राशन कार्ड से जुड़े नए नियम - 2026 से राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया और आसान की जा रही है। अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।

2. किसानों के लिए बड़े बदलाव - नए साल में किसानों से जुड़े कई अहम नियम लागू होंगे। यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी जरूरी कर दी गई है। अगर किसान आईडी नहीं होगी तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में बड़ा बदलाव होगा। खरीफ 2026 से जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी होगा।

3. बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियम- 2026 में बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदल सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। अब ज्यादा डेटा आधारित जानकारी देनी पड़ सकती है। क्रेडिट स्कोर अपडेट नियम, अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट हो जाएगा, जबकि पहले इसमें 15 दिन लगते थे। एसबीआई और अन्य बैंकों ने लोन की ब्याज दरों और एफडी रेट्स में बदलाव किया है, जिसका असर 2026 में दिखेगा।

4. सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस - 2026 से कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में टैब के जरिए डिजिटल हाजिरी दर्ज की जाएगी। इससे शिक्षकों की उपस्थिति पर बेहतर निगरानी होगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।

5. सोशल मीडिया से जुड़े नियम - सोशल मीडिया को लेकर भी सख्ती बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों की तरह अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत में भी इससे जुड़े नियम देखने को मिल सकते हैं।

6. एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें - हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 10 रुपये घटाए गए थे। 1 जनवरी 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी कटौती की उम्मीद है, जिससे आम परिवारों को राहत मिल सकती है।

7. 8वां वेतन आयोग - केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। उम्मीद है कि 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अगर घोषणा में देरी होती है, तब भी कर्मचारियों को पिछली तारीख से फायदा (एरियर) मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर बदलने से बेसिक सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी संभव है।

8. सीएनजी और पीएनजी के दाम होंगे कम - 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार द्वारा टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। जोन सिस्टम में बदलाव के कारण सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे वाहन चलाने वालों और घरेलू गैस इस्तेमाल करने वालों को राहत मिलेगी।

9. रियल एस्टेट में निवेश होगा आसान - 1 जनवरी 2026 से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को म्यूचुअल फंड द्वारा इक्विटी के रूप में माना जाएगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। छोटे निवेशकों को भी फायदा मिलेगा।

10. पैन कार्ड आधार लिंक जरूरी - 1 जनवरी 2026 तक अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। बैंक लेनदेन, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय कामों में दिक्कत आ सकती है।

बंगाल विधानसभा चुनाव में चौतरफा मुकाबले की संभावना

कांग्रेस ने छोड़ा वाममोर्चा का दामन

निज संवाददाताः बंगाल में 2026 में होने वाला काफी अहम है। इसको लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गयी है। इसी के साथ कांग्रेस व वाममोर्चा के बीच गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन बीते रविवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने वाममोर्चा के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रहे लोगों को निराश किया। उन्होंने कहा-लोग चाहते हैं कि हम अकेले लड़ें। अभी हमारे पास जो ताकत है, उससे हम अकेले जा सकते हैं। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को इस बारे में बता दिया है। जब एक पार्टी कमजोर होती है, तो वे दूसरी पार्टी को साथ लेना चाहते हैं। हम अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। इसीलिए कांग्रेस अब अकेले जाने के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। पिछला विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ी थी, जबकि कांग्रेस और वाममोर्चा एक साथ चुनाव लड़े थे और भाजपा भी चुनावी मैंदान में थी। इस बार यह आशा की जा रही थी कि कांग्रेस और वाममोर्चा एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो वाममोर्चा के साथ चुनाव लड़ने की पक्षधर नहीं है। यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो बंगाल में चौतरफा मुकाबला हो जाने की संभावना है। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ये चार पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। शुभंकर सरकार ने कहा-अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोगों की जरूरतें, नौकरी, खाना, घर, कानून और व्यवस्था, अब महत्वहीन हो गई हैं, क्योंकि कोई भी सरकार लोगों की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए, वे इनसे ध्यान हटाने के लिए छोटा धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2021 चुनाव वाममोर्चा के साथ गठबंधन में लड़ा था। आईएसएफ ने भी अलायंस बनाया था। उस समय आईएसएफ ने अपनी शुरुआत की थी। इस बार भी आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बसु को एक पत्र लिखकर कहा कि वह गठबंधन करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह भी पता चला है कि बीते शनिवार को अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बैठक हुई थी। इसमें 'सीट एग्रीमेंट' पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं थी। इसे लेकर बंगाल की सियासत में चर्चा हो रही थी। इस बीच, बीते सोमवार को शुभांकर सरकार ने गठबंधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रुख साफ कर दिया।

उन्होंने कहा-कांग्रेस अब अपने पैरों पर चलने लायक है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिटिक्स के सभी इक्वेशन (समीकरण) पोटेंशियल होते हैं। इसलिए, भविष्य में समीकरण बदल सकते हैं।

इंसाफ के नाम पर एक घटना पर शोर-शराबा, दूसरी पर खामोशी क्यों?

प्रसंग : उन्नाव रेप केस

निज संवाददाता : गत दिनों की बात है जब उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। (अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है) मगर, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्षी दल और सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर बीजेपी सरकार और उसके नेताओं पर निशाना साधने लगे। लेकिन सवाल यह है कि वही धरनाजीवी तब कहां गायब हो जाते हैं, जब समाज के दूसरे तबके से जुड़े अपराध सामने आते हैं? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक पर हिंदू महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने, यौन शोषण करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने 17 दिसंबर को नींद की गोलियां खाकर सुसाइड की कोशिश की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी फरार है, लेकिन इस मामले पर वह शोर-शराबा क्यों नहीं? केजीएमयू के इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं। आरोपी रमीजुद्दीन ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। निजी फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। सितंबर में पीड़िता गर्भवती हुई, तो आरोपी ने मेडिकल अबॉर्शन करवाया, लेकिन शोषण बंद नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि पैथोलॉजी विभाग में धार्मिक प्रवचन आयोजित कर कई महिला-पुरुष डॉक्टरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। डॉक्टरों के संगठन ने वीसी सोनिया नित्यानंद से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि मामला दबाने की कोशिश हुई। विभागाध्यक्ष वाहिद अली पर भी मुख्य भूमिका का इल्जाम है। पुलिस जांच जारी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा क्यों ठंडा पड़ा हुआ है? बहरहाल, यह पहला ऐसा मामला नहीं है। समाज में पक्षपातपूर्ण चुप्पी का सिलसिला लंबा है। याद कीजिए हुदाबिया इंटरनेशनल स्कूल मामला, जहां केरल के एक मदरसे में हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण और शोषण का आरोप लगा। 2023 में सामने आया यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन मुख्यधारा मीडिया और विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक रंग देने से बचाया। नतीजा? आरोपी आजाद घूम रहे हैं। इसी तरह, 2022 में हरियाणा के नूंह में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाने का केस दर्ज हुआ। पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ नदारद रही। इसके विपरीत, जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति या हिंदू पृष्ठभूमि का आरोपी सामने आता है, जैसे हाथरस कांड या उन्नाव केस, तो सड़कें भर जाती हैं। एक और मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2024 में एक मुस्लिम शिक्षक पर हिंदू छात्रा को मोबाइल पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास करने का आरोप लगा। पीड़िता के परिवार ने एफआईआर कराई, लेकिन स्थानीय स्तर पर ही मामला दब गया। न कोई राष्ट्रीय मीडिया कवरेज, न विपक्षी नेताओं का बयानबाजी का दौर। क्यों? क्योंकि यह संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। वहीं, बिहार के वैशाली में बीजेपी विधायक के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगते ही विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। सवाल वाजिब है कि न्याय सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? दरअसल, इस विरोधाभास की जड़ें गहरी हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण ने न्याय को भी रंग दे दिया है। जब आरोपी सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है, तो कोर्ट का फैसला सरकारी दबाव बन जाता है। लेकिन जब आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हो, तो सांप्रदायिकता फैलाने का ठप्पा लग जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में देशभर में 50,000 से ज्यादा धर्मांतरण से जुड़े शोषण के केस दर्ज हुए, जिनमें अधिकांश लव जिहाद के पैटर्न वाले थे। उत्तर प्रदेश में ही 2024 में 1,200 ऐसे केस सामने आए, लेकिन इन पर चुप्पी साधी गई।

ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच चश्मों का निःशुल्क वितरण

निज संवाददाता: राज्य की विशिष्ट सामाजिक सेवा संस्था सोसाइटी बेनिफिट सर्किल द्वारा हमीरागाछी स्थित हरिपाल अंचल में स्थापित, संस्था के चिकित्सालय से ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंदों को प्रत्येक माह की तरह चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। यह वितरण संस्था के अध्यक्ष पवन बंसल के निर्देशानुसार किया गया। प्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति रमेश सरावगी के कर कमलों से वितरण प्रारंभ हुआ। इस सुचारू व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने संस्था के सामाजिक सेवा कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उनके साथ संस्था के सदस्यगण एवं अन्य अतिथि गण ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अतिथिगण में रमेश सरावगी के साथ ऋषभ, मयंक, किरण, रिशा, शैली, मेहुल, एकांश, यथार्थ, कीवी आदि के साथ संस्था के कार्यकारिणी सदस्य सुभाष चंद्र गोयनका, अंजू गोयनका, अरुण केडिया, कमल शर्मा, चंदा शर्मा, अमित परवाल, शीतल परवाल, मेघा जगनानी, अरुण झुनझुनवाला, अनु मिश्र आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व में चक्षु परीक्षण एवं चश्मे वितरण का कार्य किया गया। उल्लेखनीय है कि संस्था अपने चिकित्सा क्षेत्र में सेवा कार्य के तहत लगातार चक्षु परीक्षण, होम्योपैथी चिकित्सा का सेवा कार्य जारी है। इसी क्रम में 76 मरीजों को चश्मा वितरण हुआ। संस्था के अध्यक्ष पवन बंसल ने सभी को धन्यवाद दिया एवं कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही कोई भी सेवा कार्य संपन्न होता है।

भारतीय नागरिक के भारत में ही शादी होने पर विदेशी अदालतें नहीं दे सकतीं तलाक

हाई कोर्ट ने दिया अहम आदेश

निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में एक अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि विदेशी अदालतें तलाक और भरण-पोषण संबंधी कार्यवाही की सुनवाई तभी कर सकती हैं जब पति-पत्नी में से कोई एक वहां का निवासी हो। हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में शादी हुई और कपल भारत का निवासी है, इसलिए विदेश की कोर्ट तलाक या मैंटीनेंस के केस में सुनवाई नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जो पत्नी के पक्ष में हुआ था। हाई कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में दिए गए ब्रिटेन के जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 15 दिसंबर को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह निर्दिष्ट है कि याचिका की सुनवाई उस निवास स्थान की स्थानीय सीमा के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय द्वारा की जा सकती है जहां दंपति अंतिम बार निवास करते थे।

पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि इसी कानून की एक अलग धारा के तहत जिला न्यायालय का अर्थ भारतीय न्यायालय है, न कि विदेशी न्यायालय, फिर भी सही अर्थ में और उदार दृष्टिकोण से ब्रिटेन के पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो सकता है यदि प्रथम दृष्टया पत्नी वहां निवास करती है और कम से कम दोनों पक्ष अंतिम बार ब्रिटेन में पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे हों।

न्यायाधीशों ने कहा कि यह सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में पत्नी द्वारा दायर तलाक के मुकदमे में अंततः जो फैसला सुनाया जाएगा, वह भारत में निर्णायक नहीं होगा। इस दंपत्ति का विवाह 15 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुआ था। पति ने सबसे पहले 4 सितंबर 2024 को अलीपुर अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी। 10 अक्टूबर 2024 को पत्नी ने ब्रिटेन की अदालत में तलाक और अगले दिन भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की। उसने बताया कि वह 2015 से छात्र और कार्य वीजा पर ब्रिटेन में रह रही थी और कभी-कभार भारत आती-जाती रहती थी। आखिरी बार वे दोनों विवाहित जोड़े के रूप में ब्रिटेन में ही रहे थे। 16 मई 2025 को ब्रिटेन की पारिवारिक अदालत ने पति को भरण-पोषण देने का आदेश दिया। हालांकि, 1 नवंबर को अलीपुर जिला अदालत ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि पत्नी ब्रिटेन में अपना मामला आगे नहीं बढ़ा सकती। अलीपुर अदालत ने तर्क दिया कि पति ने पहले तलाक का मुकदमा दायर किया था और यह माना कि ब्रिटेन की अदालत के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि पत्नी देश की स्थायी निवासी नहीं है। अदालत ने कहा कि ब्रिटेन की अदालत द्वारा दी गई भरण-पोषण राशि अत्यधिक और दमनकारी है क्योंकि यह पति की आय से अधिक है। महिला ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, जहां हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही पत्नी ने बाद में याचिका दायर की हो, पति ने ब्रिटेन की अदालत में जवाब दाखिल किया और सबूत पेश किए। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानना संभव नहीं है कि पति ब्रिटेन में पत्नी की तलाक की कार्यवाही और गुजारा भत्ता आवेदन का विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

बांग्लादेश से जान बचाकर बंगाल आए मशहूर सरोद वादक ने सुनाई दास्तां

छिपानी पड़ी भारतीय पहचान, खान सरनेम व स्थानीय भाषा बनी मददगार

निज संवाददाता : बांग्लादेश इन दिनों हिंसा व अशांति से ग्रस्त है। इस देश से पारिवारिक संबंध रखने वाले कोलकाता निवासी सरोद वादक शिराज अली खान को बीते 19 दिसंबर को ढाका के छायानट में एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देनी थी। लेकिन कार्यक्रम से कुछ ही घंटे पहले, कट्टरपंथी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद देशव्यापी अशांति के माहौल में सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। शनिवार शाम को शिराज किसी तरह कोलकाता भागने में कामयाब रहे, रास्ते में उन्होंने अपनी भारतीय पहचान छुपाई। यह फैसला उन्होंने मजबूरी में लिया था, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें लेना पड़ेगा। शिराज के पिता उस्ताद ध्यानेश खान हैं, जो उस्ताद अली अकबर खान के पुत्र और बाबा अलाउद्दीन खान के पोते हैं। उनके परदादा, उस्ताद अलाउद्दीन खान, बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया से थे। शिराज ने कहा कि कुछ साल पहले, उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम पर बने एक कॉलेज (ब्राह्मणबारिया में) पर हमला हुआ था। छायानट पर हुआ हमला हमारी संस्कृति और साझा मूल्यों पर एक अकल्पनीय हमला है। शिराज 16 दिसंबर को ढाका पहुंचे थे, जहां उन्हें अगले दिन बनानी में एक जैज़ कॉन्सर्ट में भाग लेना था। उनका प्रमुख शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम 19 दिसंबर को छायानट में होना था। शिराज ने बताया कि 17-18 लोगों की छोटी सी सभा के बावजूद, बनानी का अनुभव दिल को छू लेने वाला था। 19 दिसंबर की सुबह मुझे छायानट पर हुए हमले के बारे में पता चला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इमारत में मुझे प्रस्तुति देनी थी, वह नष्ट हो गई है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखना मेरे लिए असहनीय था, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो संगीत और उसकी पवित्रता को सर्वोच्च सम्मान देता है। टूटे हुए वाद्ययंत्रों की तस्वीरें देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी मेरा पैर किसी वाद्ययंत्र को छू जाए, तो मैं तुरंत विद्या और कला की देवी मां सरस्वती से माफी मांगता हूं। संगीत जगत और राष्ट्र को भारी क्षति हुई है। ढाका से निकलने की कोशिश करते समय शिराज को एक चेकपॉइंट पर रोक दिया गया। उन्होंने बताया-मुझसे पूछा गया कि क्या मेरे पास विदेशी मुद्रा है। सौभाग्य से, मेरे पास नहीं थी। पहली बार मैंने अपनी भारतीय पहचान का ज़िक्र नहीं किया। भारत-विरोधी भावनाओं से अवगत होने के कारण, मैंने ब्राह्मणबारिया की स्थानीय बोली में बात की। मेरी मां ब्राह्मणबारिया की रहने वाली हैं और 1968 में शादी के बाद भारत में बस गईं। मैंने उनसे यह बोली सीखी। शिराज के खान उपनाम ने मदद की। उन्होंने बताया कि लोगों को लगा कि मैं बांग्लादेश से हूं, भारत से नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी भारतीय पहचान छिपानी पड़ेगी। मैंने अपना भारतीय पासपोर्ट और फोन ड्राइवर को दे दिया, जिसने उन्हें कार के डैशबोर्ड में रख दिया। मुझे वे हवाई अड्डे पर वापस मिल गए। मुझे नहीं पता कि अगर मैंने अपनी पहचान नहीं छिपाई होती तो क्या होता। मेरी मां अभी भी बांग्लादेश में हैं, और उनके लौटने तक हम चिंतित हैं। मेरे हिंदू साथी भी ढाका में फंसे हुए हैं, और मैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके नाम नहीं बताऊंगा।

शिराज ने कहा कि जब तक कलाकारों, संगीत और सांस्कृतिक संस्थानों का सम्मान और संरक्षण नहीं होगा, तब तक वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बांग्लादेश के शिक्षित और कला प्रेमी लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी समस्या उस भीड़ की मानसिकता से है जो सांस्कृतिक संस्थानों पर हमला करती है।

बंगाल की राजनीति में खुल गया नए 'पीरजादा' का विकल्प?

हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी

निज संवाददाता : पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बीते 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी होगा। हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में खगरूपारा चौराहे पर अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी किया।

हुमायूं ने कहा कि वह दो सीटों-रेजिनगर और बेलडांगा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी हुमायूं कबीर बहुत ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, पहले वह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने की वजह से चर्चा में आए और अब उन्होंने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। उनके रूख से बंगाल में एक नई तरह की सियासत के शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर ने हाल ही में 'तृणमूल कांग्रेस विरोधी' और 'भारतीय जनता पार्टी विरोधी' ताकतों से एकजुट होने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन बनाकर और मिलकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया था। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से नई राजनीति पार्टी बनाई है। राज्य के चर्चित नेता कबीर ने यह भी कहा कि उनका काम अल्पसंख्यक वोटर्स को एकजुट करने का होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 90 सीटों पर जीत हासिल करें ताकि चुनाव के बाद मेरी पार्टी नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। वरना मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर भी राज्य में मुस्लिम समाज के हितों और उनके कल्याण की बात कर रहे हैं। हालांकि उनसे पहले बंगाल की सियासत में 2 पीरजादा की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। एक पीरजादा कांग्रेस के साथ है तो दूसरा पीरजादा सत्तारुढ़ टीएमसी के खेमे में हैं। ऐसे में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं के पास एक तीसरा खेमा बनाने का ही विकल्प दिख रहा है, क्योंकि वह बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। गौरतलब है कि 2025 के मई महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को सामाजिक कार्यकर्ता पीरजादा खोबायेब अमीन कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया। पीरजादा अमीन पश्चिम बंगाल के एक जाने-माने परिवार से ताल्लक रखते हैं। इस परिवार का पश्चिम बंगाल ही नहीं ओडिशा और त्रिपुरा में भी काफी असर देखा जाता है। अमीन का परिवार धर्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इसी तरह राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी टीएमसी ने पीरजादा अमीन के कांग्रेस में जाने के कुछ दिन बाद ही फुरफुरा शरीफ के पीरजादा कासिम सिद्दीकी को पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया। इस कोशिश को सीएम ममता की ओर से बीजेपी के ध्रुवीकरण की कोशिशों को देखते हुए मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के बढ़ते असर का मुकाबला करने के अहम रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया। कासिम सिद्दीकी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे की कवायद है कि पिछले चुनाव (2021) में मौलवी अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) लॉन्च किया था और इस नई पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया था।

फ्रंट ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अब्बास के भाई नौशाद सिद्दीकी ने दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर सीट पर जीत हासिल की थी। इस सीट को टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, जिसमें आईएसएफ ने मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। साथ ही 2 साल पहले 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान फ्रंट ने करीब 400 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल की और इनमें से ज्यादातर दक्षिण बंगाल में टीएमसी के गढ़ में थीं। इसके अलावा इस फ्रंट का आधार दक्षिण 24 परगना से निकलकर कई मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में लगातार बढ़ता जा रहा था, और यह ममता की पार्टी के लिए टेंशन की वजह बन गई। ऐसे में ममता ने कासिम सिद्दीकी को पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल कराए बगैर ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ताकि अगले चुनाव में उसके मुस्लिम वोट को दूसरी ओर जाने से रोका जा सके। फुरफुरा शरीफ में सिद्दीकी परिवार का बड़ा रसूख है। कासिम सिद्दीकी, अब्बास और नौशाद सिद्दीकी के करीबी रिश्तेदार हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में कासिम सिद्दीकी को बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है।

बंगाल में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बचा हुआ हो, लेकिन वहां पर सभी राजनीतिक दलों की ओर से ध्रुवीकरण की कोशिश तेज कर दी गई है। बीजेपी बांग्लादेश में हिंसा, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के अलावा राज्य में मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा, शर्मिष्ठा पानोली जैसे मामलों के जरिए लगातार माहौल बनाने में जुटी है। अब हुमायूं कबीर के रूप में बंगाल की राजनीति में एक नया 'पीरजादा' आ गया है जिनकी वजह से चुनावी फिजा अलग ही रंग में बनने लगी है। दो रसूखदार पीरजादाओं ने तृणमूल और कांग्रेस के साथ मिलकर अपने-अपने रास्ते तय कर लिए हैं जबकि हुमायूं कबीर अपने नाम से ही मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि, उन पर एजेंट होने और मिलीभगत जैसे आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बंगाल की राजनीति का ये नया पीरजादा, किसके लिए मुसीबत बनेगा और किसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा।

हुमायूं कबीर के बाद अब टीएमसी विधायक ने बंगाल में कृष्ण मंदिर बनाने का किया ऐलान

श्री कृष्ण मंदिर की लागत 1 करोड़ रुपए होगी

निज संवाददाता : बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है, लेकिन उससे पहले ही राज्य की राजनीति गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच टीएमसी के एक अन्य विधायक ने श्री कृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की है।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक और जाने-माने उद्योगपति जाकिर हुसैन ने घोषणा की है कि हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद के बाद अब श्री कृष्ण मंदिर बनेगा, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनेगी। उन्होंने कहा है कि गीता और कुरान में 85 फीसद समानता है।

जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद निर्वाचन क्षेत्र के जंगीपुर से टीएमसी के विधायक हैं। वो पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हुसैन निर्वाचित सदस्य और एक सफल व्यवसायी हैं। पार्टी में शामिल होने से पहले, हुसैन बीड़ी के बड़े कारोबार में थे।

वहीं बात करें हुमायूं कबीर की तो वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। इन दिनों वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हुमायूं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हुए हैं। बीते 6 दिसंबर को उन्होंने मस्जिद की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ फीता काटकर मस्जिद की नींव रखी थी। पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था।हुमायूं कबीर ने बीते दिनों ही दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वह किंगमेकर के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा था कि 2026 में न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। उन्होंने कहा था कि उनका अनुमान है कि 294 सदस्यीय विधानसभा में कोई भी पार्टी 148 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मैं किंगमेकर बनूंगा। मेरे समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता।

'बांग्लादेश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने को 1971 जैसी स्थिति को दोहराना चाहिए'

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा बयान

निज संवाददाता : भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के सही सोच वाले नागरिकों को पड़ोसी देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने और अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए 1971 जैसी स्थिति को दोहराना पड़ सकता है। शुभेंदु ने कहा कि 1971 में मुक्तिजोद्धाओं (मुक्ति योद्धाओं) ने पाकिस्तानियों को हराया था। उन्होंने साफ किया कि वह इस मुद्दे पर एक भारतीय नागरिक के रूप में टिप्पणी कर रहे हैं, न कि भाजपा नेता के रूप में। ₹

शुभेंदु ने कहा कि बांग्लादेश के सही विचार वाले लोग, जो जमाती तत्वों को हराना चाहते हैं और बंगाली संस्कृति, साहित्य की महिमा और विरासत को बहाल करना चाहते हैं तथा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें 1971 जैसी स्थिति को वापस लाने की दिशा में काम करना पड़ सकता है। शुभेंदु ने पत्रकारों से कहा कि मुक्ति योद्धाओं ने बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को परास्त किया था। आज के जिहाद-विरोधी मुक्तिजोद्धाओं के लिए शायद ऐसी ही स्थिति को दोहराना समय की मांग हो। देखते हैं क्या होता है। शुभेंदु ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार या अन्य सक्रिय राजनीतिक ताकतों की कार्रवाई से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों में विश्वास का भाव पैदा नहीं होता है। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा प्रवक्ता के तौर पर कम और भारत के नागरिक के तौर पर ज्यादा बोल रहा हूं।

कितना स्वास्थ्यकर है 1 रुपये या 5 रुपये की सस्ती कैंटीन का खाना?

बंगाल समेत कई राज्यों में चलाई जा रही है यह सेवा

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में गरीबों और मजदूरों के लिए सस्ती कैंटीन चलाई जा रही हैं। इनमें तमिलनाडु में अम्मा उनवागम (अम्मा कैंटीन) काफी फेमस है, जहां एक रुपये में इडली तो पांच रुपये में सांभर राइस मिलता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में मां कैंटीन है, जहां पांच रुपये में दाल-चावल, सब्जी और अंडा मिलता है। इसी तरह दिल्ली में भी अटल कैंटीन शुरू हो चुकी है, जहां पांच रुपये में दाल-चावल, सब्जी और रोटी की थाली मिलती है। क्या इतना सस्ता मिलने वाला खाना सच में हेल्दी होता है? जानते हैं कि इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

दिसंबर 2025 में दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर 100 अटल कैंटीन शुरू की हैं। ये कैंटीन झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और गरीब बस्तियों में हैं। यहां हर थाली की कीमत सिर्फ पांच रुपये रखी गई है, जबकि असली लागत 25-30 रुपये तक है। बाकी सब्सिडी सरकार देती है। इसके मेन्यू में दाल-चावल, रोटी (300 ग्राम तक), सब्जी (100 ग्राम) और अचार दिया जा रहा है। हर कैंटीन दिन में दो बार (सुबह-शाम) खाना देती है और करीब 1000 लोगों को थाली परोसती है। एफएसएसएआई और लैब टेस्टिंग से खाने की सफाई चेक होती है। तमिलनाडु में 2013 से चल रहीं ये कैंटीन अब भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें एक रुपये में इडली, पांच रुपये में पोंगल, पांच रुपये में सांभर-राइस, लेमन राइस और करी लीव राइस मिलते हैं। वहीं, तीन रुपये में दही राइस मिलता है। यह खाना हाइजीनिक होता है, जिसे महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप बनाते हैं।

ऐसी थालियों पर क्या है डॉक्टर की राय?

दिल्ली में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और फूड सिक्योरिटी रिसर्चर डॉ. रितिका खेरा के मुताबिक, ये कैंटीन बहुत अच्छी हैं। इनमें सरकारी स्कीम्स के तहत ताजा और गर्म खाना मिलता है, जो सड़क के ठेलों से ज्यादा हेल्दी होता है। इनकी थालियों में कार्बोहाइड्रेट्स (चावल/रोटी), प्रोटीन (दाल) और सब्जियां होती हैं, जो कुपोषण कम करने में मदद करती हैं। ये कैंटीन गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी का अच्छा तरीका हैं। ये माल्न्यूट्रिशन और हाइजीन प्रॉब्लम कम करती हैं। हालांकि, काफी समय तक सिर्फ यह खाना खाने से एनीमिया या विटामिन की कमी हो सकती है। इन कैंटीन में मिलने वाली थाली में दाल (प्रोटीन), रोटी/चावल (एनर्जी), सब्जी (विटामिन) होने चाहिए। कैंटीन एफएसएसएआई अप्रूव्ड हो। स्टाफ ग्लव्स पहनता हो और साफ पानी इस्तेमाल किया जाता हो। खाना ताजा, गर्म और स्वादिष्ट होना चाहिए। इनमें ज्यादा तेल-मसाले नहीं होने चाहिए।

पश्चिम बंगाल की मां कैंटीन कितनी बेस्ट?

पश्चिम बंगाल में 2021 से मां कैंटीन शुरू की गई थी। यहां पांच रुपये में चावल, दाल और सब्जी मिलती है। इसमें सरकार सब्सिडी देती है। यह थाली गरीबों-मजदूरों और आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए काफी मददगार साबित होती है।

'एसआईआर में किया जा रहा एआई तकनीक का इस्तेमाल'

ममता बनर्जी का बड़ा आरोप

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर प्रक्रिया के चलते करीब 60 लोगों की मौत हुई है। बुजुर्ग लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। बांकुड़ा की जनसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले वे सोनार बांग्ला का वादा करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों को पीटा जाता है। बांकुड़ा की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एसआईआर एक बहुत बड़ा घोटाला है और एआई तकनीक का इस्तेमाल करके एसआईआर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि लोग, भाजपा को पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं आने देंगे। टीएमसी प्रमुख ने धमकी देते हुए कहा, अगर मतदाता सूची से एक भी वैध मतदाता का नाम कटा तो उनकी पार्टी टीएमसी दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करेगी। जनसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था?

रवींद्रनाथ टैगोर की 'फ्रॉम अक्रॉस द डार्क' को मिले रिकॉर्ड तोड़ 10.7 करोड़

- कविगुरु ने निधन के चार साल पहले 1937 में बनाई थी यह पेंटिंग

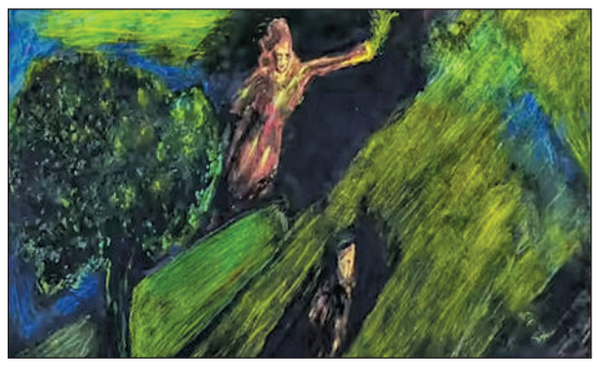

निज संवाददाता : कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941) की बनाई एक पेंटिंग 'फ्रॉम अक्रॉस द डार्क' ने ऑनलाइन नीलामी में 10.7 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कीमत हासिल की है। यह पेंटिंग टैगोर की कला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद गंभीरता से लेना शुरू किया था। यह नीलामी 14 से 17 दिसंबर तक चली और इस पेंटिंग की कीमत इसके अनुमानित मूल्य 2-3 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा रही। टैगोर की कलाकृतियों की यह रिकॉर्ड कीमत उनके निधन के चार साल पहले 1937 में बनाई गई एक पेंटिंग के लिए मिली है। यह पेंटिंग टैगोर के जीवन के उस दौर को दर्शाती है जब वे अकेलेपन और व्यक्तिगत नुकसान से गुजर रहे थे। इस पेंटिंग को मुंबई के एक संग्रह में रखा गया था। इस पेंटिंग को टैगोर ने 1937 में राजमाता विद्यावती देवी को दी थी। वह उस समय अल्मोड़ा में ठहरे हुए थे। अस्तगुरु के मार्केटिंग डायरेक्टर मनोज मंसुखानी ने बताया कि यह पेंटिंग टैगोर की पहली सार्वजनिक नीलामी में ही सबसे महंगी टैगोर कलाकृति बन गई है। इस पेंटिंग का शीर्षक 'तमोसा परास्तात' है, जिसका मतलब है 'अंधेरे से परे'। यह पेंटिंग टैगोर के जीवन के उस समय को दर्शाती है जब उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को बचपन में खो दिया था। उन्होंने राजमाता विद्यावती देवी को यह पेंटिंग उनके बच्चे की मृत्यु के बाद दी थी। ऐसा माना जाता है कि टैगोर का मानना था कि अंधेरा अंत नहीं, बल्कि जुड़ाव का रास्ता है। 'फ्रॉम अक्रॉस द डार्क' पेंटिंग में एक अकेला व्यक्ति अंधेरे में दिखाया गया है और परछाई से कोई दूसरा हाथ बढ़ा रहा है। कला समीक्षकों का कहना है कि यह पेंटिंग टैगोर के जीवन के उस दौर की मनोवैज्ञानिक गहराई को दर्शाती है, जो उम्र अकेलेपन और व्यक्तिगत नुकसान से प्रभावित थी। इस पेंटिंग के साथ एक हस्तलिखित कार्ड भी था, जिस पर 'तमोसा परास्तात' लिखा था और तारीख '5वीं आषाढ़ 1344' (19 जून, 1937) थी। कवि सुबोध सरकार ने इस पेंटिंग की 10.7 करोड़ रुपये की कीमत को 'बंगाल, भारत और कला बाजार के लिए बहुत अच्छा' बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पेंटिंग्स का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुनर्मूल्यांकन शानदार है, खासकर जब 3 करोड़ रुपये अनुमानित कीमत वाली एक कलाकृति 10 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिकी। यह पेंटिंग टैगोर की कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टैगोर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 सालों में पेंटिंग को एक जुनून बना लिया था। उन्होंने लगभग 2,500 कलाकृतियां बनाईं, जिन्हें भारत, एशिया और यूरोप में प्रदर्शित किया गया है। टैगोर को 1972 के एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेज़र्स एक्ट के तहत राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था।

एसआईआर अपडेट से बदल सकता है यूपी का चुनावी नक्शा

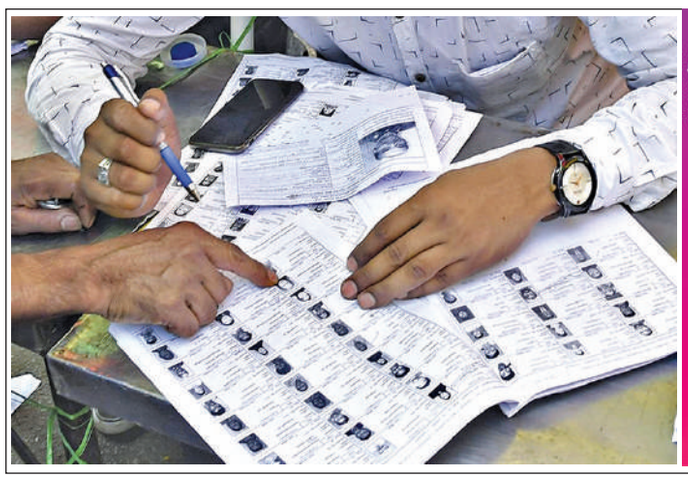

चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस और अपील का मौका दिया जाता है। आयोग का कहना है कि अंतिम सूची आने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही।

निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों मतदाता सूची के एक तकनीकी से दिखने वाले, लेकिन असर में बेहद सियासी मुद्दे के इर्द-गिर्द घूम रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि यह प्रक्रिया 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद बनती नजर आ रही है। चुनाव आयोग इसे नियमित और जरूरी कवायद बता रहा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने-अपने चश्मे से देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी फर्जी, डुप्लीकेट और घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को आशंका है कि इस प्रक्रिया की आड़ में गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी तबके के वोट काटे जाएंगे। एसआईआर की शुरुआत 1 नवंबर 2025 से हुई। जनवरी 2025 की मतदाता सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। आयोग का उद्देश्य साफ है मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और फर्जी नामों को हटाना, साथ ही नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए घर-घर सत्यापन कराया गया। यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार विवाद इसलिए गहरा गया क्योंकि सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं के बयान सियासी आग में घी डालने लगे। 14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि एसआईआर के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से करीब चार करोड़ नाम हट सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इनमें से 85 से 90 फीसदी नाम बीजेपी समर्थकों के हैं। यह बयान आते ही सियासी हलकों में खलबली मच गई। सवाल उठने लगे कि अगर वास्तव में चार करोड़ नाम हटते हैं तो यह प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। योगी के मुताबिक, अब तक करीब 12 करोड़ नाम ही रिकॉर्ड हो पाए हैं, जबकि आबादी के अनुपात में यह संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर पर सक्रिय होकर छूटे हुए नामों को जोड़वाएं। योगी के बयान के कुछ ही दिन बाद, 17 दिसंबर को पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक अलग ही दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की तीन विधानसभा सीटों में ही करीब तीन लाख नाम कट सकते हैं और ये ज्यादातर समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। यह बयान योगी के दावे से उलट दिशा में जाता दिखा। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों के नाम ज्यादा कट रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। यहीं से एसआईआर पर सवाल और गहरे हो गए। विपक्ष ने इन बयानों को हाथों हाथ लपक लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चार करोड़ नामों में 85 फीसदी बीजेपी के हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के साढ़े तीन करोड़ वोटर फर्जी थे। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर वोट काटने की साजिश रची जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। असल में, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जनवरी 2026 में आएगी और फाइनल सूची फरवरी में प्रकाशित होगी। यानी फिलहाल जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे प्राथमिक फीडबैक, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और अनुमान पर आधारित हैं। यही वजह है कि आंकड़ों से ज्यादा बयानबाजी सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ के चार करोड़ वाले दावे के पीछे जो गणित बताया जा रहा है, वह भी चर्चा में है। यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ मानी जाती है। अगर इसमें 65 फीसदी वयस्क मतदाता मानें, तो आंकड़ा करीब 16 करोड़ के आसपास बैठता है। इसमें हर साल 18 साल पूरे करने वाले नए वोटरों को जोड़ना भी शामिल है। ऐसे में 12 करोड़ नाम रिकॉर्ड होने की बात सुनकर चार करोड़ का अंतर निकालना आसान है। लेकिन यह अंतर वास्तव में नाम कटने का है या अब तक सत्यापन में न आ पाने का, यह साफ नहीं है।

बीजेपी के भीतर भी यह माना जा रहा है कि शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन गांव का वोट बनाए रखते हैं। सत्यापन के समय ऐसे कई नाम छूट जाते हैं। योगी का जोर इस बात पर था कि पार्टी कार्यकर्ता समय रहते ऐसे मतदाताओं का फॉर्म भरवाएं। उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों और उम्र में गड़बड़ी वाले उदाहरण भी आए, जिसने पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की राजनीति से जोड़ दिया। दूसरी ओर, सुब्रत पाठक का बयान कन्नौज जैसे समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ से जुड़ा है। 2019 में यहां से सांसद रहे पाठक 2024 में अखिलेश यादव से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनके बयान को स्थानीय सियासत और 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। उनका दावा है कि फर्जी और डुप्लीकेट नामों का सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है और एसआईआर के बाद उसकी असलियत सामने आ जाएगी। हालांकि, इस दावे के समर्थन में भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस और अपील का मौका दिया जाता है। आयोग का कहना है कि अंतिम सूची आने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अगर दूसरे राज्यों के अनुभव देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, जबकि मृत, डुप्लीकेट और लंबे समय से बाहर रह रहे लोगों के नाम कटे हैं। वहां किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान होने की बात साफ तौर पर सामने नहीं आई। यूपी में भी यही पैटर्न दोहराया जा सकता है, लेकिन यहां का पैमाना और सियासी दांव कहीं बड़े हैं। सवाल आखिर में यही है कि मतदाताओं की संख्या घटने या बढ़ने से फायदा किसे होगा। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किन इलाकों में, किस सामाजिक वर्ग के और किस उम्र के मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होते हैं या जुड़ते हैं। फिलहाल इतना तय है कि एसआईआर ने 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जब तक जनवरी-फरवरी 2026 में आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक योगी हों या अखिलेश, हर बयान सियासत का हिस्सा बना रहेगा और वोटर लिस्ट राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी।

संपादकीय

खालिदा ज़िया की मौत और बांग्लादेश की राजनीति पर असर

बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच ही उस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया का मंगलवार को निधन हो गया, जिससे भारत के पूर्वी पड़ोसी देश के लिए चार दशक से ज़्यादा लंबे युग का अंत हो गया। 1980 के दशक से, ज़िया और उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी, शेख हसीना, अपने देश की राजनीति में हावी रहीं। उन्होंने पहले मिलिट्री शासन के खिलाफ़ विरोध को आगे बढ़ाया, फिर देश का नेतृत्व करने के लिए मुकाबला किया। हसीना का देश निकाला और भारत में शरण लेना और उनकी पार्टी, अवामी लीग पर चुनावों से बैन के साथ, ज़िया की मौत ने देश के नेतृत्व में एक पीढ़ीगत बदलाव को मजबूर कर दिया है। उनके बेटे, तारिक रहमान, 12 फरवरी को होने वाले चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने की उम्मीद है। ओपिनियन पोल जमात-ए-इस्लामी के साथ कड़े मुकाबले का संकेत देते हैं। चुनाव जीतने के लिए, बीएनपी शायद ज़िया की विरासत पर भरोसा करेगी, कम से कम उन हिस्सों पर जिन्हें पार्टी बांग्लादेशी वोटरों को याद रखना चाहेगी। बांग्लादेशियों की पुरानी पीढ़ी के लिए, ज़िया हुसैन मुहम्मद इरशाद के मिलिट्री शासन के खिलाफ़ विरोध का चेहरा थीं। उन्होंने 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर, कांच की छत को भी तोड़ दिया, लेकिन पांच साल बाद हसीना ने उनकी जगह ले ली। 2000 के दशक में उन्होंने फिर से जगह बदल ली, उनके कार्यकाल, जो निजी दुश्मनी से पहचाने जाते थे, एक मिलिट्री-समर्थित अंतरिम सरकार द्वारा अलग हो गए। ज़िया की सरकार और परिवार जिसमें उनके बेटे तारिक रहमान भी शामिल थे पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हसीना के राज में ज़िया को जेल भी हुई और हज़ारों बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि इरशाद के राज में हुआ था, बीएनपी ने हसीना के राज में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह सही नहीं होगा। फिर भी, जब वह सत्ता में थीं, तो उन पर भी संस्थाओं को कमज़ोर करने और हसीना को निशाना बनाने के आरोप लगे। भारत के साथ उनके रिश्ते भी इसी तरह मुश्किल थे। दोनों में से कोई भी एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब ज़िया प्रधानमंत्री थीं, तो वे एक स्थिर कामकाजी रिश्ता बनाने में भी कामयाब रहे। ऐसे समय में जब बांग्लादेश राजनीतिक हिंसा और अलग-अलग धर्मों के बीच तनाव की वजह से बुरी तरह बंटा हुआ है, ज़िया की मौत एकता का एक खास पल लेकर आई है, जिसमें हसीना और अंतरिम सरकार के नेता मुहम्मद यूनुस ने दिवंगत नेता की विरासत को याद किया। बांग्लादेश के अगली पीढ़ी के नेताओं को उनकी गलतियों और उनकी हिम्मत से सीखना चाहिए।

नफरत रोकने में कारगर या अभिव्यक्ति की आजादी पर शिकंजा?

कर्नाटक का एंटी-हेट बिल

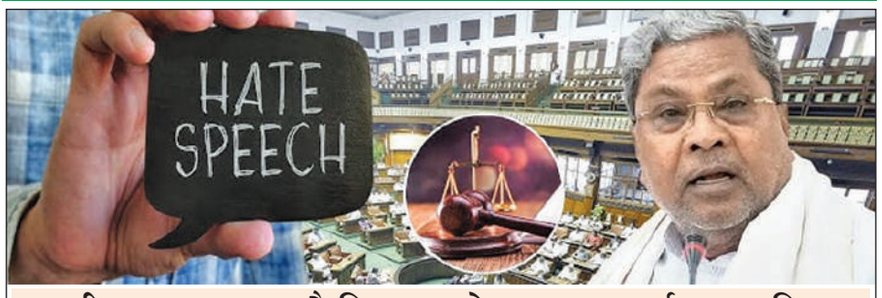

भारतीय अनुभव बताता है कि कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका निष्पक्ष और संतुलित इस्तेमाल है। अगर प्रवर्तन एजेंसियां राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करें और अदालतें सख़्ती से निगरानी रखें, तो यह कानून सामाजिक सद्भाव का औज़ार बन सकता है। लेकिन अगर इसे चुनिंदा तरीके से लागू किया गया, तो वही आशंका सच हो सकती है, जिसे आलोचक आज 'काले कानून' के रूप में देख रहे हैं।

निज संवाददाता : कर्नाटक विधानसभा से 18 दिसंबर 2025 को पारित हुआ 'कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025' सिर्फ एक नया कानून नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, राज्य की शक्ति और सामाजिक सद्भाव के बीच चल रही खींचतान का ताज़ा अध्याय बन गया है। कांग्रेस सरकार इसे समाज में बढ़ती नफरत और हिंसा के खिलाफ़ ज़रूरी औज़ार बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कई सिविल लिबर्टीज़ समूह इसे 'काला कानून' करार देकर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ख़तरा मान रहे हैं। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने हेट स्पीच को परिभाषित करते हुए अलग से व्यापक कानून बनाया है, इसलिए इसकी गूंज कर्नाटक से बाहर पूरे देश में सुनाई दे रही है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा कानूनी ढांचा नाकाफ़ी साबित हुआ है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 या आईटी एक्ट जैसे प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था पर केंद्रित हैं, न कि नफरत से प्रेरित भाषण और अपराध की जड़ों पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। 2020 में धारा 153 के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि दर महज़ 20.2 प्रतिशत रही, जबकि गिरफ्तारियां कहीं ज़्यादा हुईं। कांग्रेस का कहना है कि कम सज़ा दर का मतलब है कि नफरत फैलाने वाले अक्सर बच निकलते हैं और समाज में ज़हर घोलने का सिलसिला जारी रहता है। इसी कमी को दूर करने के लिए 1 से 7 साल और दोबारा अपराध पर 10 साल तक की सज़ा, गैर-जमानती प्रावधान और पीड़ित मुआवज़े जैसी धाराएं जोड़ी गई हैं। लेकिन विपक्ष की आपत्ति यहीं से शुरू होती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिल में हेट स्पीच की परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि सामान्य आलोचना, राजनीतिक भाषण, व्यंग्य या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी इसके दायरे में आ सकती है। नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने विधानसभा में कहा कि यह विधेयक पुलिस को 'हिटलर' बना देगा और सत्ता के हाथ में ऐसा हथियार देगा, जिससे असहमति को आसानी से कुचला जा सके। सी. टी. रवि ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बोलने की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे किसी भी सूरत में कमजोर नहीं किया जा सकता।

आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर है। गैर-जमानती अपराध होने के कारण पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। चुनावी माहौल में यह आशंका जताई जा रही है कि सत्ताधारी दल विपक्षी नेताओं के भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट को 'नफरत फैलाने वाला' बताकर एफआईआर दर्ज कर सकता है। अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं, जहां 'भारत माता की जय' जैसे नारों पर भी मामले दर्ज हुए और बाद में अदालतों ने उन्हें रद्द किया। नए कानून के तहत ऐसी कार्रवाइयों का दायरा और बढ़ सकता है। सोशल मीडिया और पत्रकारिता भी इस बहस के केंद्र में हैं। बिल राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ब्लॉक या हटाने का अधिकार देता है, वह भी बिना किसी अदालती आदेश के। आलोचकों का कहना है कि इससे खोजी पत्रकारिता, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग और सत्ता की आलोचना पर सेंसरशिप का खतरा पैदा होगा।

आईटी एक्ट की धारा 66ए को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की अस्पष्टता के कारण रद्द किया था, लेकिन नए बिल में वही शक्तियां एक अलग रास्ते से लौटती दिख रही हैं। समर्थकों की दलीलें भी कमज़ोर नहीं हैं। अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर ईसाई संगठनों ने चर्चों और धार्मिक स्थलों पर हमलों के संदर्भ में इस कानून का स्वागत किया है। उनका कहना है कि हेट स्पीच अक्सर वास्तविक हिंसा का रास्ता खोलती है और अगर शुरुआती स्तर पर सख़्त कार्रवाई हो, तो बड़े टकराव रोके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में सक्रिय रहा है।

2022 में शीर्ष अदालत ने पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और चेतावनी दी थी कि ढिलाई को अवमानना माना जाएगा। हालांकि बाद में अदालत ने यह भी माना कि हर मामले की निगरानी संभव नहीं है और असली चुनौती कानून के क्रियान्वयन में है कर्नाटक का यह बिल विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट और 2022 के निजी सदस्य विधेयक की सिफारिशों की झलक भी दिखाता है, जहां 'सेक्सुअल ओरिएंटेशन' और 'जेंडर' जैसी श्रेणियों को शामिल कर संरक्षित समूहों का दायरा बढ़ाने की बात कही गई थी। साथ ही 'सामूहिक दायित्व' की अवधारणा लाकर संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को भी जवाबदेह बनाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अपने आप में नया और विवादास्पद है, क्योंकि इससे संगठनात्मक गतिविधियों पर भी आपराधिक ज़िम्मेदारी तय हो सकती है। सल सवाल यही है कि क्या यह कानून नफरत रोकने में कारगर होगा या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सियासी शिकंजा बनेगा। भारतीय अनुभव बताता है कि कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका निष्पक्ष और संतुलित इस्तेमाल है। अगर प्रवर्तन एजेंसियां राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करें और अदालतें सख़्ती से निगरानी रखें, तो यह कानून सामाजिक सद्भाव का औज़ार बन सकता है। लेकिन अगर इसे चुनिंदा तरीके से लागू किया गया, तो वही आशंका सच हो सकती है, जिसे आलोचक आज 'काले कानून' के रूप में देख रहे हैं। कर्नाटक ने एक नई मिसाल पेश की है; अब देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि यह मिसाल लोकतंत्र को मज़बूत करेगी या बहसों को और तीखा।

खौफनाक साया

कहानी

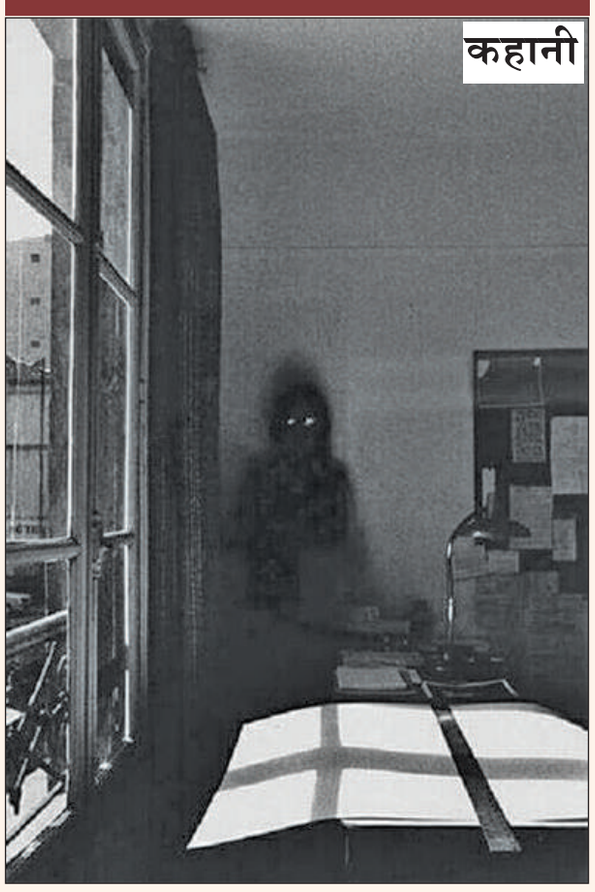

आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नयी-नयी शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोयी हुई थीं तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गयी। उन्होने तुरंत उठ कर टीवी बंद कर दिया। और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हे महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थीं उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा। लकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो, और बगल में लेट कर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थीं की यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटा कर वो बिस्तर से उठीं और पीछे पलट कर देखा. वहाँ कोई नहीं था लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी, तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की और दबा हुआ था। और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थीं पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली।

दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चली थी घबराहट में धरा ने तकिया उठा कर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आ कर ठीक हो गया। और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से उठ खड़ी हुई हों । इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई तब धरा में थोड़ी-बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सांस तुरत दौड़ कर धरा के कमरे में आ गयी। और पूछने लगी की क्या हुआ? अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देख कर उसके होश उड़ गए। धरा नें देखा की उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी उसकी आँखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। और उसका कद करीब-करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देख कर धरा वहीं बेहोश हो गयी। और उसी रात उन्हे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा।

डॉक्टर नें कहा कि डर के मारे उन्हे लो-ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं हैं इस लिए धरा आज भी अपने मायके रहती हैं।

क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का कारण:

धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। और उसके ऊपर दहेज़ की लालच में पहली पत्नी को ज़हर देकर मारने का मुक़दमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी माँ के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पायी लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालंकि उसका कहना था की पत्नी को उसने ज़हर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही ज़हर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है।

मार लो मुस्की

शराबी- तेरी दुकान कब खुलेगी
मालिक- सुबह 9 बजे
शराबी- तेरी दुकान कब खुलेगी?
मालिक- बताया ना सुबह 9 बजे !
शराबी ने फिर फ़ोन लगाकर पूछा -दुकान कब खुलेगी
मालिक बोला- अबे शराबी कितनी बार बताऊं सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे आना..
शराबी बोला: मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूं।
घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा..तभी शराबी पीछे से आया और बोला:अब दुकान खोल ही दी तो एक क्वार्टर रॉयल स्टैग की दे दे!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

एक शराबी शराब पी कर एक अर्थी से टकरा गया। बॉडी गिर गई और लोग शराबी को पीटने लगे। इस पर शराबी बोला- अबे जो गिरा वो तो कुछ नहीं बोल रहा, तुम काहे नेता बन रहे हो!!!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

अध्यापक ने गधे के सामने एक बोतल दारू रखी और एक बाल्टी पानी की, गधा सारा पानी पी गया। अध्यापक ने बच्चों से पूछा तो तुमने क्या सीखा?
बच्चे- जो दारु नहीं पीता वो गधा है।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

यार कल रात घर देर से पहुचा, बेल बजाई पर बीबी ने दरवाजा खोला ही नही! पूरी रात सडक पर गुजारी।
दोस्त: फिर सुबह बीबी की खबर ली की नही?
....नही यार, सबेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नही हुई है, और चाबी तो जेब मे थी!!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

संता लड़की देखने गया, लड़की के पिता ने पूछा, 'बेटा' शराब पीते हो?
संता बोला, ''पहले जिस काम से आया हूँ उसे देख लूँ....
फिर बैठते हैं।''

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मैं बैंक में नोट बदलवाने गया था
बैंक के क्लर्क ने पूछा: खाता है?
मैने कहा हां...पीता भी हूँ ।
क्लर्क न जाने क्यों नाराज हो गया?

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पत्नी बोली : हैलो! कहाँ हो?
विक्रम : मोटीवेट कर रहा हूँ।
पत्नी : किसे?
विक्रम : किसे क्या मतलब? तेरा वेट कर रहा हूँ एक घंटे से.. मोटी!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

एक शराबी ने हवा में सिक्का उछालते हुए दूसरे शराबी से कहा- हेड आया तो विस्की..
टेल आया तो रम..
खड़ा रह गया तो बीयर..
अगर हवा में ही रह गया तो आज से दारू पीना बंद।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

दोस्त: भाई गाड़ी चलाते समय क्या नही करना चाहिए?
मैं: शराब नही पिना चाहिए!
दोस्त: हाँ भाई हादसा हो जाएगा ना?
मैं: नही बे दारू छलक जाही त हो जाही बडा हादसा समझे!!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

शराब की दुकान पर लिखा स्लोगन - बोतल शराब की खुद 'खाली' होकर दूसरों को ''फुल'' कर देती है !!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

प्लीज ऐसे पोस्ट मत डाला कीजिये कि रिक्शा वाले की लड़की सिल्वर मेडल लाई.., रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना.., रिक्शा वाले की बेटी के 99 परसेंट आये...खबरें पढ़ पढ़ के बच्चे जिद कर रहे हैं ,, पापा आप भी रिक्शा ले लो...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

वोटर- उंगली पे स्याही लगाते है ये कितने दिन में निकलेगी?
मतदान अधिकारी- करीब 4 महीने में...!!!
वोटर (सिर आगे करते हुए)- मेरे सिर में भी लगा दीजिये,डाई सिर्फ 15 दिन ही चलती हैं...!!!
अधिकारी गुस्से में- भाग यहां से !!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

जानें अपना राशिफल

मेष
संतुलन रखकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य आपका समय खराब कर सकता है सावधान रहे, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है।

वृषभ
आसानी से काम पूरा होने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की जरूरत है।

मिथुन
व्यर्थ समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सोच समझकर ही करे, किसी पर ज्यादा भरोसा परेशानी का कारण बन सकता है, अपनी बुद्धिमानी दिखाने की आवश्यकता है, मन चंचल रहेगा।

कर्क
संघर्ष करने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, कोई परिवार का सदस्य आपका काम बिगाड़ सकता है सावधान रहे, बिना काम बाहर नहीं जाये।

सिंह
समाधान निकलने वाला समय हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, जीवनसाथी पूरा साथ दे सकते हैं।

कन्या
विश्वासघात वाला समय हो सकता है इसलिए शान्ति से दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है, किसी पर ज्यादा भरोसा परेशानी का कारण बन सकता है, बिना काम बाहर नहीं जाये घात हो सकता है।

तुला
आवश्यकता पूरा होने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी विदेश यात्रा करने पर सहमति बन सकती है, कोई बड़ा काम करने का अवसर भी मिल सकता है।

वृश्चिक
अनुकूल समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है।

धनु
षडयंत्र वाला समय हो सकता है इसलिए शान्ति से सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई परिवार का सदस्य आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है सावधान रहे, मन स्थिर रखें।

मकर
प्रयास करने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है, नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा हो सकता है, परिवार के लोग पूरा साथ दे सकते हैं।

कुंभ
मतभेद वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है, अपने विचार स्पष्ट रखकर काम करने की जरूरत है।

मीन
प्रबल समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

हल करो हीरो बनो

1. विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर शृंखला के लेखक हैं?
(क) अरुंधति राय (ख) जे.के. राउलिंग
(ग) तस्लीमा नसरीन (घ) सलमान रुश्दी
2. फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था।
(क) बाबर (ख) हुमायूं
(ग) जहांगीर (घ) अकबर
3. दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे।
(क) ब्रह्म समाज (ख) चिन्मय मिशन
(ग) आर्य समाज (घ) प्रार्थना समाज
4. कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है।
(क) राखीगड़ी (ख) धोलावीरा
(ग) लोथल (घ) कालीबंगा
5. 1930 में महात्मा गांधी का नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था
(क) नील की खेती (ख) वस्त्र व्यापार नियम
(ग) भूमि राजस्व (घ) नमक कर
6. किस कलाकार ने 1975 में मीणा गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था।
(क) सोनल मानसिंह (ख) सितारा देवी
(ग) शोवना नारायण (घ) मल्लिका साराभाई

(उत्तर इसी अंक में)

माथापच्ची-17

	2	9		5	1		7	3
		4				9		8
	5							
			5		7	1		
5		7		4		2		9
		1	3		6			
							4	
1		2				7		
8	4		9	7		3	2	

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 16 का हल

3	1	4	5	9	8	2	7	6
6	2	8	1	7	3	9	4	5
9	7	5	4	6	2	8	1	3
7	8	6	3	4	5	1	9	2
1	3	9	2	8	7	5	6	4
4	5	2	9	1	6	3	8	7
2	6	7	8	5	1	4	3	9
5	4	1	6	3	9	7	2	8
8	9	3	7	2	4	6	5	1

प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के माध्यम से 'प्रकृति की ओर लौटने' का संदेश

♦ समर्पण ट्रस्ट की पहल पर 72 से अधिक लोगों की हुई प्राकृतिक चिकित्सा

निज संवाददाता : समाज के स्वास्थ्य, संतुलन एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से निरंतर सक्रिय समर्पण ट्रस्ट द्वारा साल्टलेक, कोलकाता में आयोजित द्विदिवसीय ''प्राकृतिक चिकित्सीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर अत्यंत सफल एवं प्रभावशाली रूप में संपन्न हुआ। यह शिविर जनहित की भावना से प्रेरित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य-संबंधी पहल रहा, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से नागरिकों को तन, मन एवं आत्मा के संतुलन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, नाड़ी विशेषज्ञ एवं कायचिकित्सा विशेषज्ञ तथा मानद चिकित्सक माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल डॉ. पीयूष द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में अरुण भुवालका प्रधान अतिथि, महावीर बंका मुख्य अतिथि, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल एवं अक्षय बींजराजका विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डॉ.लक्ष्मण पल्ले, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कोनिजेती रोसैया गवर्नमेंट नेचर क्योर हॉस्पिटल, हैदराबाद अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ उपस्थित रहे। उनके मार्गदर्शन में दो दिवसीय शिविर के दौरान पूर्ति समूह के निदेशकद्वय सपत्नीक किशोर पंसारी, सपत्नीक महेश पंसारी, हंसराज बामलवा सपत्नीक, कम्फर्ट लेडी के मनोज गुप्ता सपत्नीक, बिजनेसमैन आशु सिंह, श्याम लाल अग्रवाल समेत 72 नागरिकों का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श किया गया। इस अवसर पर डा. पल्ले ने कहा कि आज के भाग दौड़ भरे जीवनशैली में आदमी यदि प्रकृति के अनुरूप जीवन का अनुशरण करे तो उसे कोई समस्या नहीं होगा। शिविर के दौरान समर्पण ट्रस्ट के सभापति दिनेश बजाज ने डॉ. लक्ष्मण पल्ले एवं उनकी टीम को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल ने कहा कि एलोपैथी से हताश निराश रोगी लगातार प्राकृतिक चिकित्सा की ओर उन्मुख हो रहे है, जो समाज के लिए एक साकारात्मक संकेत है। ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ्य जीवन व निरोगी काया के लिए प्रकृति के शरण में जाना ही श्रेयस्कर है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अभिषेक शरद ने कहा कि यह प्राकृतिक चिकित्सा शिविर ट्रस्ट की जनकल्याणकारी सोच का सशक्त उदाहरण है। ट्रस्ट के महासचिव प्रदीप ढेडिया ने आगामी समर्पण सम्मान समारोह 2026 के आयोजन के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि डा. पल्ले की लोकप्रियता व कोलकाता में उनकी बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा पुनः उनके नेतृत्व में शिविर आयोजित किया जायेगा।

शिविर के उद्घाटनकर्ता डॉ. पीयूष द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक्यूपंचर को आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा कहा जाता है। सकारात्मक और संतुलित जीवनशैली के लिए आयुर्वेद एक वरदान है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में लोग तेजी से आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र अग्रवाल ने डॉ. लक्ष्मण पल्ले के सेवा, समर्पण एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

ट्रस्ट की ओर से पंकज भालोटिया ने स्वागत वक्तव्य देते हुए कहा कि यह शिविर प्रकृति की ओर लौटने का एक सकारात्मक और समयोचित उपक्रम है। समर्पण ट्रस्ट की ओर से प्रीति ढेडिया ने ट्रस्ट की विविध गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन डॉ.जयप्रकाश मिश्र ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संजय जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। शिविर का समस्त प्रबंधन आनंद इवेंट्स द्वारा किया गया। समर्पण ट्रस्ट की यह पहल समाज में स्वस्थ, संतुलित एवं प्रकृति-आधारित जीवनशैली के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रमाण बनी। शिविर को सफल बनाने में सोमनाथ अडुकिया,अभ्युदय दुगड़, महेश भुवालका, अशोक ढेडिया, गणेश अग्रवाल, मनीष बजाज, आनंद अमन ढेडिया, पवन खेतान, अभिषेक गुप्ता समेत अन्य सक्रिय रहे।

फिलिस्तीन के हमदर्द बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार के समय कहां गायब?

अजय कुमार

हिंदुस्तान में ऐसे नेताओं और राजनैतिक दलों की कमी नहीं है, जो दुनिया के किसी कोने में मुसलमानों के साथ खड़े होने में देरी नहीं करते हैं। इजरायल जब गाजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो यहां तमाम दलों के नेता और मुस्लिम संगठन अपनी छाती पीटने और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा तो विरोध स्वरूप फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में ही पहुंच गई थीं, लेकिन इन्हें दुनिया के किसी कोने में हिन्दुओं के साथ होने वाले अत्याचार और यहां तक कि उनकी हत्या पर भी मुंह खोलने में शर्म आती है। भारत में हर समय दलितों और पिछड़ों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी या हिन्दू संगठनों पर हमलावर रहने वाले इन नेताओं को बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिन्दुओं का अत्याचार नहीं दिखाई देता है। इसे मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत का चरम कहा जा सकता है। आज देश भर में बांग्लादेश में मारे गए हिन्दू युवक की हत्या पर धरना-प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसमें अपवाद को छोड़कर कोई बड़ा मुस्लिम संगठन या फिर मुस्लिम की सियासत करने वाले नेता मौजूद नहीं हैं। यह बताता है कि हिन्दुओं के प्रति इन नेताओं का नजरिया क्या है। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव तक सभी नेता चुप्पी साधे हैं। कारण साफ है मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाने का डर। यह ओछी राजनीति दलितों-पिछड़ों की पीठ पर चढ़कर मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत सालों से करते चले आ रहे हैं। गौरतलब हो, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अगस्त 2024 से शुरू हुई हिंसा ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाया है। रिपोर्टों के मुताबिक, हजारों हिंदू घरों पर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए और महिलाओं पर अत्याचार किए गए। खासकर पिछड़े और दलित हिंदू, जैसे नमासुद्रा और अन्य जातियां, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और स्थानीय मीडिया के अनुसार, कम से कम 200 हिंदू मारे गए, जबकि संपत्ति का नुकसान करोड़ों डॉलर का है। इनमें दलित हिंदू समुदायों पर फोकस करें तो तस्वीर और भयावह है। बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ये लोग पहले से ही गरीबी और भेदभाव का शिकार हैं। हिंसक भीड़ ने उनके गांवों को जला दिया, महिलाओं का अपहरण किया। फिर भी भारत के दलित नेता चुप हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को खराब नहीं करना है। यह पाखंड साफ दिखता है, जब ये नेता घरेलू चुनावों में दलित कार्ड खेलते हैं। न्याय की दुहाई देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं। 'भारत जोड़ो यात्रा' में उन्होंने दलितों के घर भोजन किया, न्याय यात्रा निकाली। लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदुओं का नरसंहार? एक शब्द भी नहीं। संसद में या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं। क्या कारण है? असल में राहुल की चुप्पी रणनीतिक है। 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने मुस्लिम-दलित गठबंधन पर दांव लगाया। अब बांग्लादेश मुद्दा उठाने से वह गठबंधन टूट सकता है। याद कीजिए, जब मणिपुर हिंसा हुई तो राहुल ने तुरंत दौरा किया, लेकिन बांग्लादेश? सन्नाटा। यह दलितों की राजनीति नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति है। दलितों की पीठ पर सवार होकर मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश तक, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला उनका हथियार रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनावों में उन्होंने मुस्लिम-यादव गठजोड़ को मजबूत किया। लेकिन बांग्लादेश के दलित हिंदुओं पर अत्याचार? अखिलेश की जुबान को लकवा मार गया। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का लगभग 40 प्रतिशत वोट मुस्लिमों का है। अखिलेश ने कभी बांग्लादेश हिंसा का जिक्र नहीं किया। बल्कि वे राम मंदिर पर आक्षेप करते हैं, ताकि मुस्लिम खुश रहें। दलित नेता मायावती को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया। लेकिन असली सवाल अगर दलितों का हक बांग्लादेश में कुचला जा रहा है, तो चुप्पी क्यों? यह पिछड़ों की ओछी राजनीति है, जहां हिंदू दलितों को भुला दिया जाता है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चंद्रशेखर आजाद खुद को भीम आर्मी का योद्धा बताते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ वे सड़कों पर उतरे, दलित युवाओं को भड़काया। लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार? उनकी आंखें बंद हैं। चंद्रशेखर ने नागरिकता संशोधन कानून को दलित-विरोधी बताया, जबकि बांग्लादेश के दलित हिंदू शरणार्थी बनने को तैयार हैं। नगीना, उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। मुस्लिम वोट के लालच में वे हिंदू दलितों के मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के दलितों का दर्द उन्हें न दिखाई देता है, न सुनाई। यह साफ है कि उनकी क्रांति सिर्फ वोट के लिए है, न कि सच्चे दलित हित के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव बिहार में मुस्लिम-यादव फॉर्मूला चलाते हैं। पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण किया। तेजस्वी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों को लुभाया, लेकिन बांग्लादेश? एक ट्वीट भी नहीं। बिहार में 17 प्रतिशत मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। तेजस्वी की चुप्पी सामरिक है। वे नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों का मुद्दा इसलिए नहीं छूते कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाता है। याद कीजिए, जब रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो लालू-तेजस्वी ने शोर मचाया। लेकिन हिंदू दलितों पर? चुप्पी। यह पिछड़ों की राजनीति का काला सच है। ये सभी नेता दलित-पिछड़ों को वोट बैंक मानते हैं, लेकिन असली खतरे पर चुप रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 20 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गई है। दलित हिंदू सबसे कमजोर हैं। भारत सरकार ने शरणार्थियों को आश्रय दिया, लेकिन विपक्ष चुप है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट 18 से 20 प्रतिशत है, जो चुनाव का रुख पलट सकता है यह दोहरा मापदंड है। देश में दलित आरक्षण की बात, लेकिन विदेश में दलित हिंदुओं का नरसंहार? अनदेखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के पश्चिम बंगाल और 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इन नेताओं की चुप्पी की खास वजह है। दलित संगठन जैसे भीम आर्मी भी मुस्लिम गठबंधन के चक्कर में हैं। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी ने रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं के माध्यम से बांग्लादेश मुद्दा उठाया। दलित-पिछड़े नेता अगर मुस्लिम तुष्टिकरण छोड़ें, तो हिंदू दलितों का भला हो सकता है। बांग्लादेश सरकार से जवाब मांगा जाए, शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून का लाभ दिया जाए। वरना यह ओछी राजनीति जारी रहेगी। दलितों को समझना होगा कि उनकी पीठ पर चढ़ने वाले ये नेता असल में वोट के भूखे हैं। बांग्लादेश का दर्द उठाओ, तभी सच्ची क्रांति आएगी।

हांसी: इतिहास के केंद्र से हाशिये तक और फिर जिले की दहलीज़ पर

डॉ. प्रियंका सौरभ

इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, वह धीरे-धीरे करवट लेता है। हरियाणा की प्राचीन नगरी हांसी इसका जीवंत उदाहरण है। एक समय यह नगर सत्ता, प्रशासन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता था। आज वही हांसी, जिसने सदियों तक शासन का भार उठाया, लंबे समय तक प्रशासनिक उपेक्षा झेलने के बाद एक बार फिर जिले के रूप में अपनी पहचान पाने की ओर अग्रसर हुई है। वर्ष 2025 में हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि इतिहास के एक अधूरे अध्याय को पूरा करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। अंग्रेजों के भारत आगमन से बहुत पहले हांसी का गौरव अपने चरम पर था। जॉर्ज थॉमस के दौर में हांसी हरियाणा क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्थापित थी। उस समय यह नगर दिल्ली परगना के अधीन उत्तरी भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल था। हांसी से ही प्रशासनिक आदेश जारी होते थे और आसपास के बड़े भूभाग पर शासन संचालित किया जाता था। यह नगर केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सैनिक रणनीतियों का भी प्रमुख केंद्र था।

मुगल काल में भी हांसी का महत्व कम नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल के ऐतिहासिक दस्तावेज़ों और नक्शों में हांसी को एक महत्वपूर्ण मुगल केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। यहां एक टकसाल स्थापित थी, जहां सिक्कों का निर्माण होता था। किसी भी नगर में टकसाल का होना उसकी आर्थिक और प्रशासनिक ताकत का प्रतीक माना जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि हांसी केवल एक कस्बा नहीं, बल्कि उस दौर की अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ था।

हांसी की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान की ओर जाने वाले मार्गों पर स्थित होने के कारण यहां मुगलों ने सैनिक छावनी स्थापित की। बाद में अंग्रेजों ने भी इसी सामरिक महत्ता को समझते हुए यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी। हांसी की किलेबंदी, प्रशासनिक ढांचा और सैन्य व्यवस्था इसे उत्तरी भारत के सुरक्षित और संगठित नगरों में शामिल करती थी।

लेकिन इतिहास की दिशा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ बदल गई। हांसी और आसपास के क्षेत्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। यह क्षेत्र उन इलाकों में शामिल था जहां अंग्रेजों को सबसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय जनता, सैनिकों और जमींदारों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं था, बल्कि उनकी सत्ता के लिए सीधी चुनौती था।

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रतिशोध की नीति अपनाई। जिन क्षेत्रों ने सबसे अधिक प्रतिरोध किया, उन्हें प्रशासनिक रूप से कमजोर किया गया। हांसी भी इसी नीति का शिकार बना। भले ही हांसी से जिले का दर्जा छीने जाने की कोई सटीक और प्रमाणिक तारीख उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 1870 से 1880 के बीच अंग्रेजों ने हांसी से जिला मुख्यालय हटाकर हिसार को नया जिला बना दिया। इसके साथ ही हांसी का प्रशासनिक महत्व लगभग समाप्त कर दिया गया। हिसार को जिला बनाकर अंग्रेजों ने न केवल प्रशासनिक ढांचा बदला, बल्कि हांसी की ऐतिहासिक भूमिका को भी हाशिये पर डाल दिया। फतेहाबाद, सिरसा जैसे इलाकों पर हिसार से शासन चलाया जाने लगा। यह बदलाव केवल सुविधा के नाम पर नहीं था, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र को नियंत्रित करने की रणनीति थी, जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का साहस दिखाया था। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास हरियाणा, पंजाब से अलग एक विशिष्ट भू-राजनीतिक पहचान के साथ नक्शों में मौजूद था। उस दौर के कई नक्शे आज भी उपलब्ध हैं, जिनमें हांसी को हरियाणा की राजधानी के रूप में दर्शाया गया है। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाकर पूरे इलाके पर शासन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हांसी का महत्व किसी एक शासक या काल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहा।

स्वतंत्रता के बाद 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तब हिसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। उस समय हांसी एक बार फिर उम्मीद कर रहा था कि उसे उसका ऐतिहासिक दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक संतुलनों के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसके बजाय हिसार जिले का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

1972 में भिवानी को अलग जिला बनाया गया। इसके बाद 1975 में सिरसा और 1997 में फतेहाबाद को जिला का दर्जा मिला। 2016 में भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी नया जिला बना। इन सभी विभाजनों ने हिसार के प्रशासनिक नक्शे को लगातार बदला और छोटा किया, लेकिन हांसी हर बार जिले की सूची से बाहर रह गया। इस उपेक्षा ने धीरे-धीरे हांसी में असंतोष को जन्म दिया। लोगों को लगने लगा कि यह केवल प्रशासनिक अनदेखी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का विस्तार है। पिछले लगभग दस वर्षों से हांसी को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। स्थानीय सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। यह मांग धीरे-धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेने लगी। हांसी के लोग यह तर्क देते रहे कि यह नगर ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिकतीनों दृष्टियों से जिला बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। यहां पहले से ही कई प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं। आसपास के क्षेत्रों की दूरी और जनसंख्या दबाव को देखते हुए भी जिला बनना तर्कसंगत माना गया। लेकिन इन सभी दलीलों से ऊपर एक भावनात्मक पहलू भी थाहांसी को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाने की आकांक्षा। 2025 में जब हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा हुई, तो इसे केवल एक प्रशासनिक खबर के रूप में नहीं देखा गया। यह घोषणा हांसी के इतिहास, संघर्ष और प्रतीक्षा की परिणति मानी गई। लोगों ने इसे उस अन्याय के आंशिक सुधार के रूप में देखा, जो 1857 के बाद अंग्रेजों ने किया था और जिसे स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक अनदेखा किया गया। हांसी का जिला बनना प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही यह निर्णय क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूत करेगा। इतिहास गवाह है कि जिन नगरों को सत्ता के केंद्र से हटाया गया, वे केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हाशिये पर चले जाते हैं। हांसी भी लंबे समय तक इसी स्थिति से गुजरा। लेकिन अब जिला बनने के साथ ही यह नगर एक बार फिर केंद्र में लौटने की तैयारी कर रहा है। हांसी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल किताबों में दर्ज घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करता है। हांसी को जिला बनाना इस बात का प्रमाण है कि इतिहास चाहे देर से ही सही, लेकिन अपनी न्यायपूर्ण दिशा जरूर खोज लेता है। आज जब हांसी जिले की दहलीज़ पर खड़ा है, तो यह केवल एक प्रशासनिक इकाई का विस्तार नहीं, बल्कि उस नगर की आत्मा की पुनर्स्थापना है, जिसने कभी हरियाणा को राजधानी दी थी, जिसने सत्ता को चुनौती दी थी और जिसने लंबे समय तक उपेक्षा सहकर भी अपनी पहचान नहीं खोई। हांसी का यह नया अध्याय इतिहास के उसी पुराने गौरव से जुड़ता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी।

हांसी एक नज़र में

प्राचीन पहचान: जॉर्ज थॉमस के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र की राजधानी
मुगल काल: अकबर के समय प्रमुख प्रशासनिक केंद्र, यहां टकसाल स्थापित
सामरिक महत्व: मुगल और अंग्रेजी दौर में सैनिक छावनी
1857 का विद्रोह: अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध, प्रशासनिक दंड मिला
जिला दर्जा छीना गया: लगभग 1870-80 के बीच हांसी से जिला मुख्यालय हटाया गया
हिसार जिला बना: हांसी, फतेहाबाद व सिरसा हिसार के अधीन आए
हरियाणा गठन (1966): हिसार सबसे बड़ा जिला
हिसार का पुनर्गठन:
1972 भिवानी अलग
1975 सिरसा अलग
1997 फतेहाबाद अलग
2016 चरखी दादरी अलग
2025 : हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा
मांग की अवधि : पिछले लगभग 10 वर्षों से निरंतर आंदोलन

हांसी कभी हरियाणा क्षेत्र की राजधानी रही है। जॉर्ज थॉमस के शासनकाल में यह प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। मुगल काल में यहां टकसाल और सैनिक छावनी स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध के कारण हांसी से जिला दर्जा छीना गया और लगभग 1870-80 के बीच हिसार को जिला बनाया गया। 1966 में हरियाणा गठन के बाद हिसार का कई बार पुनर्गठन हुआ। 2025 में हांसी को पुनः जिला बनाने की घोषणा हुई, जिसे ऐतिहासिक न्याय के रूप में देखा जा रहा है।

आर्य समाज कलकत्ता का 140 वां वार्षिकोत्सव संपन्न

डा. अरविन्द सेठ

आर्य समाज कलकत्ता का 140 वां वार्षिकोत्सव बीते 23 से 28 दिसंबर 2025 तक काली सिंधी पार्क (शिमला व्यायाम समिति) 9बी लेन कोलकाता 6 (बालिका शिक्षा सदन के निकट) में हर्षोल्लास से मनाया गया। आयोजन में आमंत्रित विद्वानों स्वामी आर्यवेश जी (दिल्ली), आचार्य योगेश भारद्वाज (मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर-प्रदेश), आचार्य आनंद पुरुषार्थी (होशंगाबाद मध्य-प्रदेश), संदीप आर्य गिल भजन उपदेशक (मेरठ) के साथ स्थानीय विद्वानों पंडित योगेशराज उपाध्याय, पंडित देवव्रत तिवारी, आचार्या अर्चना शास्त्री, पंडित राहुल देव शास्त्री, पंडित वेद प्रकाश शास्त्री, पंडित मधुसूदन शास्त्री, आचार्य दीपक कुमार पात्रा,

आचार्य वेदवीर शास्त्री के प्रवचन हुए। इस कार्यक्रम के जरिए कोलकाता महानगर वासियों के लिए वेद-वेदांगो की चर्चा सरल और सहज भाषा में सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद गुरुकुल (मालिग्राम), कन्या निर्माण गुरुकुल (लालुआगेडिया), महर्षि दयानंद आर्य गुरुकुल (कोलाघाट), वैदिक कन्या गुरुकुल (कोलाघाट), गुरुकुल फारबिसगंज (बिहार), नन्दकुमार वैदिक संस्कृति संस्थान (नन्दकुमार), वैदिक शिशु गुरुकुलम् (सालबनी) के सभी विद्यार्थीयों और आचार्यगणों ने विशेष आमंत्रित गुरुकुलों का प्रतिनिधित्व किया। 6 दिवसीय अथर्ववेद पारायण यज्ञ (संपूर्ण) में 38 यजमान दंपत्तियों ने आहुतियां प्रदान की। 23 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे विशाल शोभा यात्रा के साथ इस भव्य आयोजन का शुभारंभ हुआ। शोभायात्रा घोड़ों और रथों से सुसज्जित होकर भजन, उद्घोष, बैंड पार्टी के विशेष धुनों के साथ गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों द्वारा विशेष और आकर्षक वैदिक सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के साथ आर्य समाज कलकत्ता से प्रारंभ होकर विवेकानंद रोड, गिरीश पार्क, गणेश टॉकीज, बड़ाबाजार के विभिन्न अंचलों से होती हुई एमजी रोड क्षेत्र में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार और आयोजन की सूचना-प्रसारण के साथ काली सिंधी पार्क तक पूरी हुई। प्रतिदिन प्रात 6 से 7 बजे तक पतंजलि योगपीठ द्वारा योग शिविर, 7:30 से 9:30 बजे तक अथर्ववेद पारायण यज्ञ एवं 9:30 बजे से 11:30 बजे तक भजन व उपदेश के कार्यक्रम वैदिक विद्वानों द्वारा संपन्न किया गया। 24 दिसंबर को आर्य स्त्री समाज कोलकाता द्वारा विशेष महिला सत्संग का आयोजन किया गया। आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई। 25 दिसंबर को वेद सम्मेलन और 26 दिसंबर को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर को द्वारका प्रसाद जायसवाल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। 28 दिसंबर को अथर्ववेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ऋषि लंगर का आयोजन किया गया था। प्रधान दीपक आर्य और मंत्री ध्रुवचंद जायसवाल जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और शांति पाठ के साथ इस उत्सव का समापन हुआ।

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग सगाई

निज संवाददाता : सांसद व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, रेहान वाड्रा ने सात साल से डेट कर रहे अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया। अवीवा ने इस रिश्ते को मंज़ूरी दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को लेकर अपनी सहमति जता दी है। सूत्रों के अनुसार, अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है। रेहान और अवीवा की शादी की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि शादी से

जुड़ा फैसला दोनों परिवार आपसी सहमति और सुविधा के अनुसार करेंगे। अवीवा बेग भी एक फोटोग्राफर हैं। पिछले पांच वर्षों में अवीवा बेग ने कई प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है। वर्ष 2023 में उन्होंने मेथड गैलरी के साथ यू कैनॉट मिस दिस प्रदर्शनी में अपने काम को पेश किया। इसी साल इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम के तहत भी यू कैनॉट मिस दिस प्रदर्शनी में उनकी कला देखने को मिली। इससे पहले वर्ष 2019 में द क्रोरम क्लब में आयोजित द इल्यूज़री वर्ल्ड और 2018 में इंडिया डिजाइन आईडी, के इंडिया में भी उन्होंने अपनी फोटोग्राफी प्रदर्शित की थी। अवीवा बेग फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी एटेलियर 11 की सह-संस्थापक भी हैं। यह कंपनी देशभर की कई एजेंसियों, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी।

भारतीय मूल की महिला सीईओ ने किया कमाल

कमाई के मामले में सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को पीछे छोड़ा

निज संवाददाता: जब भी कॉर्पोरेट जगत में सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय मूल के सीईओ की बात होती है, तो आमतौर पर गूगल के सुंदर पिचाई या माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला का नाम सबसे पहले लिया जाता रहा है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल चुकी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय मूल की एग्जीक्यूटिव का खिताब अब जयश्री उल्लाल के नाम दर्ज हो गया है। हारुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, एरिस्टा नेटवर्क्स की चेयरपर्सन और सीईओ जयश्री उल्लाल ने कमाई के मामले में सुंदर पिचाई और सत्य नडेला दोनों को पीछे छोड़ दिया है और वह भारतीय मूल की दुनिया की सबसे अमीर एग्जीक्यूटिव बन गई हैं। हारुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारतीय मूल के शीर्ष एग्जीक्यूटिव्स की सूची में जयश्री उल्लाल अब संपत्ति के लिहाज से सबसे ऊपर हैं। वह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और पिछले करीब 17 वर्षों से एरिस्टा नेटवर्क्स का नेतृत्व कर रही हैं। वर्तमान में वह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सांता क्लारा में रहती हैं, जहां एरिस्टा नेटवर्क्स का मुख्यालय भी स्थित है। यह कंपनी क्लाउड नेटवर्किंग, हाई-स्पीड स्विचेज और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड नेटवर्किंग समाधान डिजाइन करती है, जिनका उपयोग बड़े डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और एंटरप्राइज ऑफिस नेटवर्क्स में व्यापक रूप से किया जाता है। जयश्री उल्लाल की संपत्ति में आई तेज बढ़ोतरी के पीछे एरिस्टा नेटवर्क्स का लगातार मजबूत प्रदर्शन एक बड़ी वजह है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जयश्री उल्लाल ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हासिल की। आगे चलकर उन्होंने 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। जयश्री उल्लाल सितंबर 2008 में एरिस्टा नेटवर्क्स से जुड़ी थीं और तब से लगातार कंपनी की सीईओ बनी हुई हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने क्लाउड और हाई-परफॉर्मेंस नेटवर्किंग के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई। एरिस्टा नेटवर्क्स से पहले वह कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकी हैं, जिनमें सिस्को सिस्टम्स, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (एएमडी) और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर शामिल हैं। इन कंपनियों में काम करने के दौरान उन्हें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बड़े पैमाने के नेटवर्क सिस्टम्स की गहरी समझ हासिल हुई, जिसका लाभ उन्होंने एरिस्टा नेटवर्क्स को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी कंपनी बनाने में सफलतापूर्वक उठाया।

भाजपा की राजनीति युवा कंधों पर, कांग्रेस में परिवारवाद और वरिष्ठता हावी

युवाओं को केवल भाषण नहीं चाहिए, उन्हें अवसर, नेतृत्व और भविष्य की स्पष्ट तस्वीर चाहिए जो कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर युवा नेतृत्व की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2025 में बिहार के मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश है। भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य की राजनीति युवाओं के कंधों पर लड़ी जाएगी।

निज संवाददाता : राहुल गांधी जब भी सार्वजनिक मंच से बोलते हैं, तो ऐसा आभास देते हैं मानो अगला प्रधानमंत्री बनना अब बस औपचारिकता भर रह गया हो। लेकिन सियासत भावनाओं से नहीं, आंकड़ों और नतीजों से चलती है। 2014, 2019 और 2024 तीन लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और तीनों में जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद वे उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते दिखते हैं। राजनीति में रिटायरमेंट की कोई तय उम्र नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में जनता बार-बार किसी नेता को नकार दे, तो वह खुद एक बड़ा संकेत होता है। राहुल गांधी आज 55 वर्ष के हैं। अगर वे किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था में होते, तो अगले पांच साल में रिटायरमेंट की तैयारी शुरू हो जाती। राजनीति में वे रिटायर नहीं होंगे, लेकिन उनके सामने जो खतरे खड़े हो रहे हैं, वे अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रहे। राहुल गांधी के स्वभाव और राजनीतिक शैली पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

नकारात्मक राजनीति उनके भाषणों का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। कभी ''चौकीदार चोर है'', कभी ''वोट चोर'', कभी ''गद्दी छोड़ो'' हर चुनाव के बाद नया नारा, लेकिन नतीजा वही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उन्हें हर हाल में ''चोर'' ही नजर आती है। समस्या यह नहीं कि वे सवाल उठाते हैं, समस्या यह है कि जनता को उनके सवालों में समाधान नहीं दिखता। विपक्ष की भूमिका निभाने और वैकल्पिक नेतृत्व देने के बीच जो फर्क होता है, राहुल गांधी आज भी उसी रेखा को नहीं पकड़ पाए हैं। बीते महीनों में कांग्रेस के भीतर से ही जो आवाजें उठी हैं, वे राहुल गांधी की राजनीति के लिए नए खतरे का संकेत देती हैं। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम का पत्र कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं से कटती जा रही है और नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। इसी पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर भी इशारों-इशारों में कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने आत्ममंथन करने के बजाय मोकीम को निष्कासित कर दिया। यह वही पुरानी कांग्रेस है, जो आईना दिखाने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। इंडिया गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असहजता अब खुलकर दिखने लगी है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ''वोट चोरी'' के आरोपों को सार्वजनिक तौर पर खारिज कर दिया। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के बाद ही नेतृत्व परिवर्तन की बात कह चुकी हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे नेता भी निजी बातचीत में यही संकेत देते रहे हैं कि कांग्रेस को अब आत्मकेंद्रित राजनीति छोड़नी होगी। सवाल साफ है अगर अपने ही सहयोगी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो देश कैसे करेगा? राहुल गांधी खुद को युवाओं का नेता बताने की कोशिश करते हैं। वे जेन-जी की बात करते हैं, आंदोलन की वकालत करते हैं, सोशल मीडिया पर युवाओं को संबोधित करते हैं। लेकिन 2029 में जब अगला लोकसभा चुनाव होगा, तब राहुल गांधी 59 वर्ष के होंगे। जेन-जी वह पीढ़ी है, जिसकी उम्र आज 13 से 28 वर्ष के बीच है। यह मान लेना कि 60 के करीब पहुंचा नेता किशोरों और युवाओं की मानसिकता का नेतृत्व करेगा, सियासत की हकीकत से आंख चुराने जैसा है। युवाओं को केवल भाषण नहीं चाहिए, उन्हें अवसर, नेतृत्व और भविष्य की स्पष्ट तस्वीर चाहिए जो कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर युवा नेतृत्व की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है।

दिसंबर 2025 में बिहार के मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश है। भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य की राजनीति युवाओं के कंधों पर लड़ी जाएगी। संगठन से लेकर सरकार तक, 50 से 55 वर्ष की उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव ये सभी चेहरे दिखाते हैं कि भाजपा लंबी राजनीतिक पारी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की हालत इसके ठीक उलट है। सचिन पायलट जैसे नेता सालों से इंतजार में हैं। कर्नाटक में डीके शिवकुमार आज भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। शशि थरूर को लोकप्रियता के बावजूद किनारे रखा गया। कन्हैया कुमार जैसे नेता इस्तेमाल से ज्यादा उपेक्षा के शिकार हुए। नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, जयवीर शेरगिल जैसे युवा चेहरे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। कांग्रेस आज भी वरिष्ठता और परिवारवाद की दीवार में उलझी हुई है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को युवा चेहरा कहा जाता है, लेकिन पार्टी के भीतर अंतिम फैसले आज भी सोनिया गांधी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। कर्नाटक संकट हो या संगठनात्मक फेरबदल, आखिरी नजर उन्हीं पर जाती है। यह स्थिति उस पार्टी की है, जो खुद को लोकतंत्र की संरक्षक बताती है। कांग्रेस का अंदरूनी कलह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से टकराव, बिना सहयोगियों को भरोसे में लिए राष्ट्रीय रैलियां, गठबंधन धर्म की अनदेखी ये सब राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष को जोड़ने का दावा करने वाले नेता के कदम अगर खुद बिखराव पैदा करें, तो खतरा स्वाभाविक है।

सबसे बड़ा खतरा उम्र नहीं, बल्कि समय से तालमेल न बैठा पाना है। भाजपा जहां युवाओं को आगे कर रही है, वहीं कांग्रेस बूढ़ों की फौज बनती जा रही है। राहुल गांधी चाहे जितना युवा दिखने की कोशिश करें, सच्चाई यही है कि पांच साल बाद वे भी उसी कतार में होंगे, जिसकी ओर मोकीम ने अपने पत्र में इशारा किया था। भारतीय राजनीति अब धैर्य नहीं, दिशा मांगती है। जनता को सपना नहीं, रोडमैप चाहिए। राहुल गांधी आज भी संघर्ष और शिकायत के बीच फंसे हुए हैं। अगर यही रफ्तार रही, तो आने वाले सालों में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा विरोधी नहीं, बल्कि समय साबित होगा।

बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर विश्व की बेशर्म खामोशी

संजय सक्सेना

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को ज़बरदस्ती गिराने के बाद वहां हिंदू समुदाय पर हो रही बर्बरता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हिन्दुओं पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलता नज़र आ रहा है। हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में करीब दो सौ हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, उनकी करोड़ों की संपत्ति लूटी जा चुकी है और हिंदू लड़कियों व महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं। भारत सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बड़े देश और मीडिया क्यों इस पर गंभीर नहीं हो रहे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त से फरवरी 2025 तक इक्कीस हिंदुओं की हत्या हुई और एक सौ बावन मंदिरों पर हमले किए गए। पिछले दो महीनों में ही 76 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें लूटपाट, घरों पर आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार शामिल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 281 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 183 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। हाल ही में दीपू दास नामक हिंदू युवक को ईशनिंदा के झूठे आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, जबकि वहां की पुलिस कह रही है कि उसके पास दीपू दास के खिलाफ ईशनिंदा का कोई सबूत नहीं है, जिससे भारत में जन आक्रोश फैल गया। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं।

जहां तक भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है, इसकी बात की जाए तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार सबसे पहले बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बना सकती है। उच्च स्तरीय वार्ताओं के ज़रिए बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा के ठोस कदम उठाने की मांग की जा सकती है, जैसा कि विदेश सचिव की यात्रा में किया गया। दूसरे विकल्प के रूप में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना संभव है, जहां बांग्लादेश पर वैश्विक दबाव बन सके। तीसरा, मानवीय सहायता कार्यक्रम शुरू करके हिंदुओं को भोजन, चिकित्सा और शरण प्रदान की जा सकती है। चौथा, बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों पर नजर रखी जा सकती है और उनके भारत-विरोधी एजेंडे को

बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर विश्व की बेशर्म खामोशी

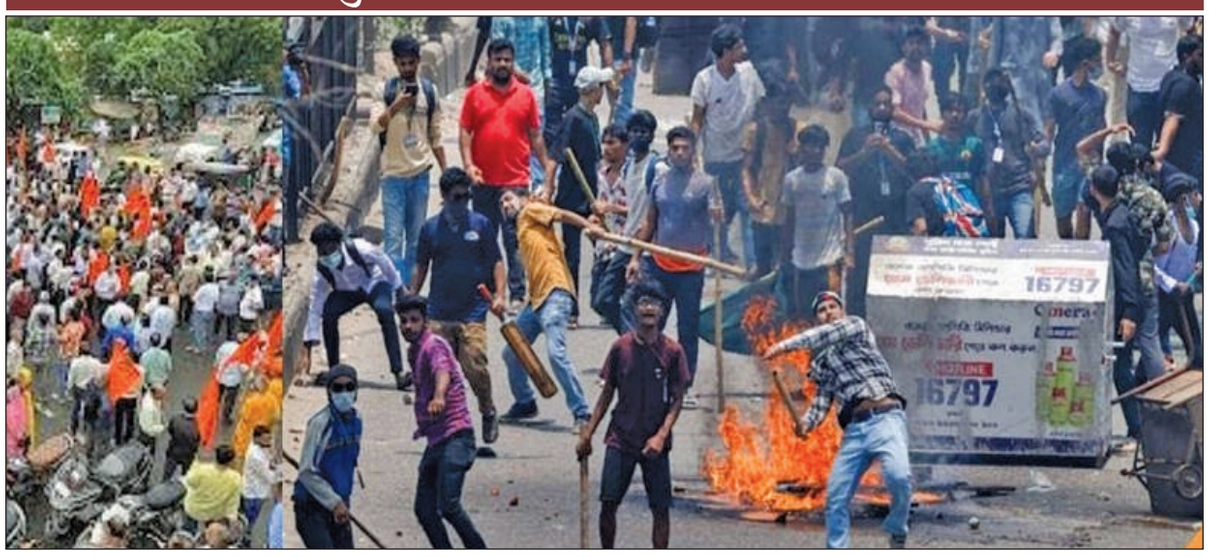

पूरे घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय मीडिया और बड़े देशों की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा पर चिंता जताई और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नस्लीय हमलों की निंदा की, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ बयान दिए, लेकिन वे कमजोर रहे। अमेरिकी सांसदों ने दीपू दास हत्याकांड की निंदा की, पर व्यापक विरोध नहीं हुआ। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच चुप हैं, जबकि अन्य संकटों पर वे मुखर रहते हैं।

रोकने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। पांचवां विकल्प आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से ईंधन, बिजली, कपास, दवाइयां और खाद्यान्न मंगाता है। इनकी आपूर्ति पर शर्तें लगाकर या अस्थायी रोक लगाकर दबाव बनाया जा सकता है, बिना आम जनता को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। छठा, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाकर हिंदू शरणार्थियों को सुरक्षित प्रवेश देकर उनकी सहायता की जा सकती है। ये सभी कदम क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखते हुए प्रभावी साबित हो सकते हैं। वैसे मोदी सरकार पहले ही बांग्लादेश के साथ अपनी चिंताएं साझा कर चुकी है और उच्चायोग वहां स्थिति पर नज़र रख रहा है। दिसंबर 2024 में बांग्लादेश ने कहा कि 1282 घटनाओं की जांच में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये कदम अपर्याप्त हैं, क्योंकि हिंसा थम नहीं रही। भारत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए दोनों देशों के हिंदू-मुस्लिम समुदायों में भाईचारा बढ़ा सकता है। साथ ही, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की शर्त पर अल्पसंख्यक सुरक्षा को बांध सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य सहायता या संयुक्त अभियान की तैयारी भी रखी जा सकती है, हालांकि फिलहाल कूटनीति को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बांग्लादेश की आम जनता पर बोझ न पड़े। ये विकल्प भारत की मानवीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

पूरे घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय मीडिया और बड़े देशों की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा पर चिंता जताई और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नस्लीय हमलों की निंदा की, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ बयान दिए, लेकिन वे कमजोर रहे। अमेरिकी सांसदों ने दीपू दास हत्याकांड की निंदा की, पर व्यापक विरोध नहीं हुआ। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच चुप हैं, जबकि अन्य संकटों पर वे मुखर रहते हैं। इसका कारण धार्मिक पूर्वाग्रह माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू पीड़ित होने पर वैश्विक सहानुभूति कम मिलती है। उधर, पश्चिमी मीडिया ने हिंसा को कमतर आंका या फर्जी खबरों का हवाला देकर टाला। बीबीसी जैसे चैनलों ने सोशल मीडिया पोस्ट को झूठा बताया, जबकि घटनाएं सिद्ध हैं। अमेरिका की चुप्पी शेख हसीना विरोध से जुड़ी है, जिन्हें उन्होंने तानाशाह कहा था। यूरोपीय देशों ने भी हसीना की धर्मनिरपेक्ष छवि को नकार दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी पुरानी सरकार पर उंगली उठाई गई, वर्तमान हिंसा पर कमज़ोर। यह दोहरा मापदंड हिंदुओं के खिलाफ वैश्विक उपेक्षा को दर्शाता है। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार के चलते हिंदू आबादी घट रही है और कट्टर ताकतें मजबूत हो रही हैं। ऐसे में भारत को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कूटनीति से आगे बढ़कर आर्थिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाना ज़रूरी है। दुनिया के अन्य देश विरोध में मुखर नहीं हो रहे क्योंकि उनके हित मुस्लिम बहुल देशों से जुड़े हैं। लेकिन भारत की मजबूत नीति से स्थिति सुधर सकती है। हिंदू समुदाय की सुरक्षा न केवल पड़ोसी का कर्तव्य है, बल्कि सभ्यता का प्रश्न है। सरकार के विकल्पों का सही इस्तेमाल ही बांग्लादेश में शांति ला सकता है।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1.जे.के. राउलिंग, 2. अकबर, 3.आर्य समाज, 4. राखीगढ़ी, 5.नमक कर, 6.मल्लिका साराभाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर विंग का बड़ा एक्शन

23 लाख शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाए 7130 करोड़

निज संवाददाता : केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर विंग (आई4सी) ने अक्टूबर 2025 तक देशभर में साइबर ठगी को रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया। इतना ही नहीं जांच एजेंसियों ने 23 लाख शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर लोगों के करीब 7130 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाए हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 31 अक्टूबर तक 11.14 लाख से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई (आईएमईआई) नंबरों को ब्लॉक किया गया। अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 32 लाख से ज्यादा म्यूल बैंक खाते बंद किए गए हैं। म्यूल बैंक अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल अपराधी गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। बड़ी बात यह कि सरकारी तंत्र की सक्रियता से डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर अपराधों में पिछले एक साल में भारी कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की आई4सी विंग के मुताबिक, साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अभूतपूर्व रही है। ठगों द्वारा इस्तेमाल होने वाले तकनीकी संसाधनों को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2025 तक की गई कार्रवाई में फर्जी दस्तावेजों पर आधारित सिम कार्ड्स को ब्लाक किया गया। इसके साथ ही ठगी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल हैंडसेट्स के आईएमईआई नंबर भी ब्लैकलिस्ट किए गए है। 32 लाख से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स बंद होने से अपराधियों के लिए पैसों को ठिकाने लगाना अब दिक्कत भरा है। सरकारी आंकड़ों में डिजिटल अरेस्ट के द्वारा होने वाली ठगी में जबरदस्त सुधार हुआ है। अक्टूबर 2024 में जहां डिजिटल अरेस्ट के 12,836 मामले सामने आए थे, वहीं अक्टूबर 2025 में यह संख्या घटकर महज 2,653 रह गई है। ठगी गई रकम में भी भारी कमी आई है। पिछले साल ठगों ने इस तरीके से 184 करोड़ की चपत लगाई थी, जो अब घटकर सिर्फ 78 करोड़ रह गई है।

महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ की ठगी मामले में शातिर बदमाश गिरफ्तार

निज संवाददाता : डिजिटल अरेस्ट के मामले में पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला नवंबर साल 2024 का है। पटना के कदमकुआं इलाके में रहने वाली एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को साइबर फ्रॉड ने फोन किया। उसने महिला से कहा कि आपने एसबीआई से क्रेडिट कार्ड से अप्लाई किया था। उस कार्ड से 1.15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। यह बात सुनते ही महिला काफी घबरा गई। फ्रॉड ने इसके बाद महिला प्रोफेसर की बात एक फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी से कराई।फर्जी अधिकारी ने महिला को धमकाते हुए फर्जी अरेस्ट वारंट भेज दिया और कहने लगा कि अब आपके खाते की जांच होगी। ठगों ने महिला को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान फर्जी अधिकारी ने महिला को एक अकाउंट नंबर दिया और कहा कि आपके खाते में जितना भी पैसा है, उसे इस खाते में ट्रांसफर कीजिये। आरबीआई इसकी जांच करेगा, सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद आपको एनओसी मिलेगी।महिला प्रोफेसर ने 48 घंटे में अपनी तीन एफडी तोड़कर 3 करोड़ रुपए ठग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।

दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की खौफनाक कहानी

जिसने भारतीयों के लिए जारी किया था देश छोड़ने का फरमान

♦ सत्ता में रहते हुए ईदी अमीन ने न सिर्फ अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार किए, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं

निज संवाददाता : इतिहास में कई तानाशाह हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अफ्रीकी देश युगांडा का शासक ईदी अमीन उन्हीं में से एक था। उसकी क्रूरता इतनी भयावह थी कि उसे मैड मैन ऑफ अफ्रीका कहा जाने लगा। सत्ता में रहते हुए उसने न सिर्फ अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार किए, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। ईदी अमीन 1971 में सैन्य तख्तापलट के जरिए युगांडा की सत्ता पर काबिज हुआ। सत्ता संभालने के एक साल बाद उसने अचानक एक अजीब फरमान जारी किया। अगस्त 1972 में उसने दावा किया कि उसे सपने में ईश्वर का आदेश मिला है कि एशियाई मूल के लोगों को युगांडा से बाहर निकाल दिया जाए। उसने भारतीय मूल के लोगों को सिर्फ 90 दिन का समय दिया। जो नहीं गया, उसे जेल या मौत की धमकी दी गई। करीब 90 हजार भारतीयों को अपना सब कुछ छोड़कर देश छोड़ना पड़ा। ये वही लोग थे जो युगांडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे। उनके जाने से देश की आर्थिक हालत पूरी तरह चरमरा गई। गौरतलब है कि ईदी अमीन का शासन सिर्फ आठ साल चला, लेकिन इस दौरान युगांडा में डर और मौत का साया छाया रहा। बताया जाता है कि उसके शासनकाल में कथित रूप से दो लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। विरोधियों को बिना किसी मुकदमे के उठा लिया जाता और फिर कभी वापस नहीं लौटाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि ईदी अमीन को मरे हुए लोगों के साथ रहना पसंद था। उसने कई नेताओं के कटे हुए सिर अपने घर में रखे और उन्हें देखकर बातें करने की चर्चा सामने आई। उसके अत्याचार इतने अमानवीय थे कि आज भी इतिहासकार उन्हें शब्दों में बयान करने से डरते हैं। ईदी अमीन ने विकलांग लोगों को समाज पर बोझ बताकर हजारों लोगों को नील नदी में फिकवाने का आदेश दिया। मगरमच्छों से भरी नदी में लोगों को जिंदा फेंक दिया गया। उसके शासन के अंत के बाद युगांडा में सामूहिक कब्रें, सड़ी हुई लाशें और खून से सने इलाके मिले, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबोको इलाके में हुआ था। उसने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की थी। शुरुआत में वह ब्रिटिश सेना में रसोइया था, बाद में सैनिक बना।

शारीरिक ताकत के दम पर उसने बॉक्सिंग और खेलों में नाम कमाया और सेना में तेजी से ऊपर चढ़ता गया। 1971 में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे को हटाकर खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यहीं से युगांडा के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। ईदी अमीन ने तंजानिया समेत कई पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोल ली। उसकी आक्रामक नीतियों के कारण युगांडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया। आखिरकार तंजानिया की सेना और विद्रोही गुटों ने मिलकर उसे सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि उसका शासन खत्म हो गया, लेकिन उसकी हैवानियत की कहानियां आज भी दुनिया के सबसे खौफनाक अध्यायों में गिनी जाती हैं।

अजब-गजब

40 साल में समुद्र में चौथी बार दिखा बेहद दुर्लभ ऑक्टोपस

वीडियो सामने आने के बाद समुद्री जीवविज्ञान की दुनिया में बढ़ी उत्सुकता

निज संवाददाता : हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास मॉन्टेरी बे में समुद्र की सतह से करीब आधा मील नीचे, अंधेरे और रहस्यमय पानी में एक बेहद दुर्लभ ऑक्टोपस कैमरे में कैद हुआ है। खास बात यह है कि इंसानों ने इस प्रजाति को पिछले 40 वर्षों में सिर्फ चार बार ही देखा है। इसका वीडियो सामने आने के बाद समुद्री जीवविज्ञान की दुनिया में उत्सुकता और रोमांच दोनों बढ़ गए हैं। इस अनोखे जीव का वैज्ञानिक नाम हालीफोरॉन अटलांटिकस है, जिसे आमतौर पर 'सेवन-आर्म ऑक्टोपस' कहा जाता है। नाम से भले ही लगे कि इसके केवल सात हाथ होते हैं, लेकिन हकीकत में इसके आठ हाथ होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नर ऑक्टोपस का आठवां हाथ प्रजनन के लिए इस्तेमाल होता है और वह इसे अक्सर छिपाकर रखता है। इसी कारण यह देखने में सात हाथों वाला प्रतीत होता है। अपने अजीब स्वरूप और विशाल आकार के कारण यह ऑक्टोपस सामान्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग नजर आता है। यह दुर्लभ नजारा मॉन्टेरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 6 नवंबर को रिकॉर्ड किया। इसके लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी आरओवी का इस्तेमाल किया गया, जो गहरे समुद्र में जाकर वीडियो और तस्वीरें कैद करता है। यह ऑक्टोपस करीब 700 मीटर की गहराई पर देखा गया, जिसे समुद्र की 'ट्वाइलाइट जोन' कहा जाता है। यह ऐसा इलाका है जहां सूरज की रोशनी लगभग नहीं पहुंचती और जीवन बेहद रहस्यमय होता है। वीडियो में यह विशाल ऑक्टोपस एक रेड हेलमेट जेलीफिश को पकड़े हुए नजर आया। यह जेलीफिश खुद भी एक बायोल्यूमिनेसेंट जीव है, जो अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पहले जब भी इस ऑक्टोपस को देखा गया, तब भी यह इसी तरह के नरम और जिलेटिनस जीवों को खाते हुए पाया गया था। इससे यह पुष्टि होती है कि इतना विशालकाय होने के बावजूद यह प्रजाति हल्के, जेल जैसी संरचना वाले जीवों पर ही निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रजाति की मादा खास तौर पर बेहद बड़ी होती है। इसकी लंबाई 13 फीट तक हो सकती है और वजन करीब 75 किलो तक पहुंच सकता है। आकार के लिहाज से यह दुनिया के सबसे बड़े ऑक्टोपस में गिनी जाती है। इतने बड़े शरीर के बावजूद इसका भोजन हल्का होना वैज्ञानिकों के लिए आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दुर्लभ ऑक्टोपस का दिखना इस बात का संकेत है कि गहरे समुद्र में अब भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं।

देश का अनोखा रेलवे स्टेशन : नवापुर

♦ टिकट मिलता है महाराष्ट्र में और ट्रेन पकड़नी पड़ती है गुजरात से

निज संवाददाता : नवापुर रेलवे स्टेशन देश का अनोखा स्टेशन है। जहां के यात्री टिकट महाराष्ट्र से खरीदते हैं और ट्रेन गुजरात से पकड़ते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस स्टेशन पर रखी बेंच आधी महाराष्ट्र और आधी गुजरात की है। यहां की एक-एक ईंट और पटरी दो राज्यों के बीच बंटी हुई है। हम बात कर रहे हैं नवापुर रेलवे स्टेशन की, जहां मुसाफिर एक ही पल में दो राज्यों की सैर कर लेते हैं। अगर आप भी कुछ अलग और मजेदार देखना चाहते हैं, तो इस स्टेशन के नजारे आपको हैरान कर देंगे। नवापुर रेलवे स्टेशन की लोकेशन बहुत दिलचस्प है। इसका महाराष्ट्र वाला हिस्सा नंदुरबार जिले में पड़ता है, जबकि गुजरात वाला हिस्सा तापी जिले की सीमा में आता है। यह स्टेशन मुंबई-दिल्ली की मुख्य रेल लाइन पर स्थित है, इसलिए यहां से गुजरने वाली ट्रेनों और यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। यहां आकर आपको एहसास होता है कि राज्यों की सीमाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर कितनी करीब हो सकती हैं। भारत में हजारों रेलवे स्टेशन हैं, कोई अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है तो कोई अपनी भीड़ के लिए। लेकिन नवापुर रेलवे स्टेशन की कहानी सबसे हटके है। यह स्टेशन ठीक महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा (बॉर्डर) पर बना हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है कि स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है और आधा गुजरात में। यही वजह है कि यहां आने वाला हर यात्री इस बात को लेकर रोमांचित रहता है कि वह कब एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। नवापुर स्टेशन को जो चीज सबसे ज्यादा मजेदार बनाती है, वह है यहां का काम करने का तरीका। दरअसल यहां मुसाफिर महाराष्ट्र की तरफ बनी खिड़की से अपना टिकट खरीदते हैं, लेकिन ट्रेन में सवार होने के लिए उन्हें गुजरात की सीमा तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहां तक कि प्लेटफॉर्म पर रखी कुर्सियां भी बंटी हुई हैं, जिनका आधा हिस्सा एक राज्य में है और आधा दूसरे में। इतना ही नहीं इस स्टेशन पर होने वाले अनाउंसमेंट भी दो अलग-अलग भाषाओं में होते हैं, जो पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। यह स्टेशन आज का नहीं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। जब इस रेलवे लाइन को बिछाया गया था, तब राज्यों की सीमाएं वैसी नहीं थीं जैसी आज हैं। बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और महाराष्ट्र व गुजरात अलग हुए, तो यह स्टेशन ठीक बॉर्डर के बीचों-बीच आ गया। रेलवे ने इसकी इस ऐतिहासिक और अनोखी पहचान को आज भी बरकरार रखा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नवापुर स्टेशन मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस तक हर तरह की ट्रेनें रुकती हैं। मुसाफिर अक्सर उस खास पीली रेखा को देखना नहीं भूलते, जो स्टेशन के बीचों-बीच खींचकर दोनों राज्यों को अलग करती है। वैसे, नवापुर अकेला ऐसा स्टेशन नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित भवानी मंडी स्टेशन भी इसी तरह दो राज्यों का मजा एक साथ देता है। लेकिन नवापुर का अपना एक अलग ही स्वैग और संस्कृति है, जो इसे भारत का सबसे यादगार रेलवे स्टेशन बनाती है।

स्वास्थ्य

कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी

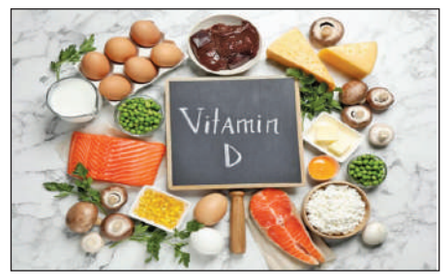

निज संवाददाता : वर्तमान समय में घर-परिवार में अक्सर किसी न किसी को पीठ दर्द, घुटनों के दर्द या चलने-फिरने में दिक्कत की शिकायत रहती है। गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बर्साइटिस, अर्थराइटिस या पेजेट रोग जैसी बीमारियां सामने आने लगती हैं। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर लंबे इलाज या सर्जरी तक की सलाह दे देते हैं। हड्डियों से जुड़ी इन समस्याओं की जड़ केवल कैल्शियम की कमी होती है। यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। कई लोग बचपन से दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पादों का सेवन करते आ रहे होते हैं, इसके बावजूद उन्हें रीढ़ और जोड़ों से जुड़ी परेशानियां घेर लेती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या है। असल में रीढ़ की हड्डी और जोड़ों की सेहत के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बल्कि विटामिन डी भी उतना ही अहम होता है। ये दोनों मिलकर ही हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी कई कशेरुकाओं से बनी होती है, जो आपस में एक खास तरल पदार्थ, साइनोवियल द्रव, के जरिए जुड़ी रहती हैं। यही द्रव जोड़ों को चिकनाई देता है और उन्हें आसानी से हिलने-डुलने में मदद करता है। हड्डियों को मजबूती देने में अस्थि मज्जा की भी बड़ी भूमिका होती है, जो हड्डियों के भीतर गहराई तक कैल्शियम और फास्फोरस पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हड्डियों में कैल्शियम का सही अवशोषण तभी संभव है, जब शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो, तो अच्छा आहार और दवाएं भी अपेक्षित असर नहीं दिखा पातीं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, जो मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से बनता है और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को करीब 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। कैल्शियम और विटामिन डी का संयुक्त प्रभाव रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़ी कई समस्याओं से बचाव और राहत देने में बेहद कारगर माना जाता है। विटामिन डी मांसपेशियों में होने वाली अकड़न को कम करने में भी मदद करता है और गर्दन, कंधों व पीठ के दर्द से राहत दिलाता है। वहीं इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और मुलायम होने लगती हैं।

इस स्थिति में जोड़ों का साइनोवियल द्रव भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और हड्डियों से चिपकने लगता है। नतीजतन जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है और हालत ज्यादा बिगड़ने पर घुटनों के ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैल्शियम और विटामिन डी को सप्लीमेंट के बजाय प्राकृतिक स्रोतों से लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, सत्तू और रागी को आहार में शामिल करना चाहिए।

मीठा नहीं, कुछ आदतें देती हैं डायबिटीज की बीमारी को बुलावा

निज संवाददाता : वर्तमान समय में आगे बढ़ने की होड़, काम का दबाव और समय की कमी तन और मन दोनों को प्रभावित कर रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि शरीर धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आ रहा है। इन्हीं बीमारियों में डायबिटीज आज सबसे तेजी से फैलने वाली समस्या बन चुकी है, जो अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज को लेकर आम धारणा यही है कि यह सिर्फ मीठा खाने से होती है, जबकि हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, जिसमें रोजमर्रा की गलत आदतें अहम भूमिका निभाती हैं। यह बीमारी तब होती है जब शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है।

इसका सीधा संबंध पैंक्रियाज से होता है, जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन जब पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या बिल्कुल नहीं बनाता, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और डायबिटीज की समस्या पैदा हो जाती है। सिर्फ मीठा ही नहीं, बल्कि गलत समय पर खाया गया भोजन भी डायबिटीज को बढ़ावा देता है। बाहर का तला-भुना और अस्वच्छ खाना, जंक फूड, मैदा से बने खाद्य पदार्थ और डिब्बाबंद चीजों का अधिक सेवन इस बीमारी के प्रमुख कारणों में शामिल है। ये सभी चीजें शरीर में शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाती हैं और इंसुलिन पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। आज की जीवनशैली में शारीरिक गतिविधि भी काफी कम हो गई है। ज्यादातर लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और चलना-फिरना बेहद सीमित हो गया है। कम गतिविधि की वजह से शरीर रक्त में मौजूद शर्करा का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे शुगर लेवल बढ़ने लगता है और इंसुलिन का असंतुलन पैदा हो जाता है। यही स्थिति धीरे-धीरे डायबिटीज का रूप ले लेती है। नींद की कमी भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। नींद हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को री-स्टार्ट करने का काम करती है। पर्याप्त नींद न मिलने से हार्मोनल असंतुलन होता है, जिसका असर इंसुलिन पर पड़ता है।

इसके अलावा लगातार तनाव लेना भी डायबिटीज को बुलावा देने जैसा है। तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। बार-बार खाने की आदत भी इस बीमारी का एक बड़ा कारण है। पेट को भोजन पचाने में करीब दो घंटे का समय लगता है। इस बीच दोबारा खाने से इंसुलिन को आराम नहीं मिल पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी बनाकर ही डायबिटीज से बचाव संभव है। बदलती जीवनशैली ने इंसान को सुविधाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन सेहत के मोर्चे पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो संतुलित खानपान मिल पा रहा है और न ही नियमित व्यायाम के लिए समय निकल पाता है।

जब परीक्षा केंद्र पर गूंजी किलकारी

परीक्षा देने आई महिला ने एग्जाम सेंटर में ही दिया सुंदर से नन्हें को जन्म

निज संवाददाता : बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में उस समय एक अनोखा और भावुक पल देखने को मिला, जब परीक्षा केंद्र पर अचानक नवजात बच्चे की किलकारी गूंज उठी। दरअसल स्नातक (बीए) की परीक्षा देने आई एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वहां मौजूद महिला कर्मचारियों के सहयोग से उसने कॉलेज परिसर में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस घटना के बाद पूरे कॉलेज में खुशी और संवेदना का माहौल बन गया। मामला रोसड़ा के थतीया गांव स्थित शशि कृष्णा कॉलेज का है, जहां बीए की परीक्षा आयोजित की जा रही थी। बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी शिवम कुमार की पत्नी रविता कुमारी परीक्षा देने पहुंची थीं। रविता हसनपुर प्रखंड के शकरपुरा भारद्वाज कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं और गर्भवती होने के बावजूद परीक्षा देने आई थीं। परीक्षा के दौरान ही रविता को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति को भांपते हुए परीक्षा ड्यूटी में तैनात महिला कर्मियों ने सूझबूझ और संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत रविता को परीक्षा हॉल से बाहर निकालकर एक खाली क्लास रूम में ले गईं। इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन को सूचना दी गई और एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था की गई। हालांकि एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही महिला कर्मियों के सहयोग से रविता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही कॉलेज परिसर में किलकारी गूंज उठी, जिसे सुनकर वहां मौजूद शिक्षक, कर्मचारी और परीक्षार्थी भावुक हो उठे। अब वही परीक्षा केंद्र चर्चा का केंद्र बन गया है। बाद में एम्बुलेंस के पहुंचने पर जच्चा और बच्चा दोनों को रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी तरह की चिंता की बात नहीं है।

रोमांटिक अदायगी व मखमली आवाज की बेजोड़ मिसाल

राजेश खन्ना-किशोर कुमार की यादगार जोड़ी

गोविन्द अग्रवाल

70 के दशक में लाखों दिलों पर बेरोकटोक राज करते रहे किशोर कुमार और राजेश खन्ना के रूह को छूते आनंद बख्शी के बोलों पर सचिन देव बर्मन के नायाब रोमांटिक धुनों पर मेरे सपनों की रानी ... से लेकर रूप तेरा मस्ताना... की गूंज आज भी संगीतप्रेमियों को दीवाना कर देती है।

कहना न होगा कि किशोर कुमार की रोमांटिक मखमली आवाज़ और राजेश खन्ना की रोमांटिक अदायगी के दीवानापन ने उन्हें सातवें आसमान पर उछाल दिया। अव्वल तो उस ज़माने में दोनों का चोली-दामन का अटूट साथ हो चला था।

किशोर कुमार और राजेश खन्ना 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा के दो सबसे हरदिल अजीज़ अदाकार और गायक थे। उन्होंने कई फिल्मों और गानों में साथ काम किया, जिनमें से कई सुपर-डुपर हिट हुए। आइए, हम उनके कुछ सदाबहार हिट गानों का जिक्र करते हैं। किशोर कुमार की अनोखी आवाज़ और बेमिसाल अंदाज़ में गाये गीतों को सेल्यूलॉयड पर राजेश खन्ना ने जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही वजह है, इन दोनों की जोड़ी 70 के दशक में सबसे आगे निकल गयी थी। क्लासिक गानों की सरगमी कतार में मेरे सपनों की रानी से लेकर रूप तेरा मस्ताना तक को एक अलग ही मुकाम हासिल हो गया था। ग़ौरतलब है, आराधना के बाद तो किशोर कुमार और राजेश खन्ना में से किसी को पीछे मुड़ कर देखने की फ़ुरसत ही नहीं मिली।

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना

राजेश खन्ना उर्फ़ काका उर्फ़ जतीन खन्ना की पैदाइश 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुई थी। राजेश खन्ना का कॅरियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, में चार दशक से अधिक समय तक फैला रहा। काका को अक्सर बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, उनके 1970 के दशक के दौरान असाधारण लोकप्रियता के कारण। सनद रहे, उन्होंने बॉलीवुड की कुछ सबसे शानदार फिल्मों में अभिनय करते हुए बुलंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये। मसलन कटी पतंग (1971), आनंद (1971), अमरप्रेम (1972) और नमकहराम (1973)। यह वक़्त का सितम ही था कि अपने दौर के बेताज बादशाह रहे राजेश खन्ना अनचाही तन्हाई और मायूसी से जूझते हुए जुलाई 2012 को 69 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गये।

दो सुपरस्टार्स का अजेय संगम

किशोर कुमार और राजेश खन्ना का ऐसा अटूट तालमेल था, जिन्हें कोई आइंदा डिगा ही नहीं पाया। उनकी जोड़ी में एक बेलौस केमिस्ट्री थी, जो किसी और अभिनेता-गायक जोड़ियों से मेल नहीं खाती थी। इसीलिए उनके फिल्मी गीत हमेशा दर्शकों के बीच बेइंतहा सराहे जाते रहे। चाहे वह रोमांटिक हो या दर्दभरे नग़मे। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गीतों में मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, अगर तुम ना होते, ये शाम मस्तानी, ये रेशमी ज़ुल्फ़ें ये शरबती आंखें, ज़िंदगी कैसी है ये पहेली, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना शामिल हैं। इनमें से हर एक गीत अपने आपमें एवरग्रीन होने के साथ ही सालों से फैंस के पसंदीदा गानों में शुमार हैं। किशोर कुमार और राजेश खन्ना की साझेदारी को खास बनानेवाली बात यह थी कि वे एक-दूसरे की सबसे उम्दा खूबियों को अनायास ही सिल्वर स्क्रीन पर उकेर दिया करते थे। किशोर कुमार की रूमानी आवाज़ का शिद्दत से राजेश खन्ना की संज़ीदगी में घुलमिल कर दो ज़िस्म एक जान का एहसास करवाना मामूली बात नहीं। साथ मिल कर उन्होंने पर्दे पर वाकई तिलिस्मी भंवर बना दिये थे, जिन्हें आज भी उनके फैंस जेहन-ओ-दिल में संजोये हुए हैं।

मेरे सपनों की रानी

यह गीत फिल्म आराधना से है और यह राजेश खन्ना के सबसे मशहूर गानों में से एक है। यह एक रोमांटिक गीत है, जो प्रेमी के अपने सपनों की प्रेमिका के प्रति प्यार और आदर को व्यक्त करता है, जिसे वह अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। वह उसे बतौर अपने सपनों की रानी देखता-समझता है और उसे अपना बनाने की ख़्वाहिश ज़ाहिर करता है। यह गीत राजेश खन्ना के खिंचाव और सम्मोहन का सिंबल बन गया है और किशोर कुमार की रेशमी रोमांटिक आवाज़ इस गाने की बेपनाह ख़ूबसूरती को चार चांद लगा देती है।

एक अजनबी हसीना से

यह गाना फिल्म अजनबी से है, जिसे किशोर कुमार ने गाया है। यह गाना एक रोमांटिक गीत है, जिसमें पुरुष मुख्य पात्र एक रहस्यमयी और दिलफ़रेब अजनबी से अपनी मुलाकात का वर्णन करता है, जिसने उसका दिल जीत लिया है। वह उसे और क़रीब से जानने की इच्छा व्यक्त करता है और उसके प्यार और स्नेह की फ़रियाद करता है। कोमल और मधुर धुन, किशोर कुमार की कशिश से लबरेज़ आवाज़ के साथ इस गाने को बॉलीवुडी संगीतप्रेमियों के बीच हमेशा पसंदीदा बना देती है।

ये जो मोहब्बत है

यह गाना फिल्म कटी पतंग से है और इसे आर. डी. बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। जिसे किशोर कुमार ने गाया था। यह साउंडट्रैक फिल्म की तरह ही बेइंतहा लोकप्रिय हो गया। इस फिल्म के तमाम गाने ऐसे थे, जो अनायास ही क्लासिक्स के क्लास में शामिल हो गए। कहना न होगा कि इस गाने को उसके ऑइकॉनिक म्यूजिक वीडियो के लिए आज भी ख़ूब याद किया जाता है। जिसमें मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना थे, जो अपने आकर्षक और रोमांटिक अदाकारी के लिए जाने जाते थे।

ज़िंदगी का सफर

यह गाना 1970 की सुपरहिट हिंदी फिल्म सफ़र का एक क्लासिक हिंदी गाना है, जिसमें गायक किशोर कुमार और राजेश खन्ना का ख़ूबसूरत आपसी तालमेल नज़र आता है। यह जीवन की यात्रा के उतार-चढ़ाव पर एक मार्मिक प्रतिबिंब है। कल्याण जी- आनंद जी की दर्द उड़ेलती धुन और दिल को छू लेनेवाला इंदीवर का भावुक कर देता ज़िंदगी का सफर है ये कैसा सफ़र इस फिल्म में जड़ा एक नगीना-सा है, जो आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है।

हमें तुमसे प्यार कितना

यह गाना 1981 की बॉलीवुड फिल्म क़ुदरत का एक क्लासिक हिंदी गाना है, जिसमें किशोर कुमार की भावपूर्ण आवाज़ और राजेश खन्ना की आकर्षक उपस्थिति ने इसे एक प्रिय हिट बना दिया है, जिसे बॉलीवुड संगीतप्रेमी आज भी संजोये हुए हैं। इस गाने में राजेश खन्ना और किशोर कुमार का अनुपम आपसी सहयोग देखते ही बनता है। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है कि किशोर कुमार और राजेश खन्ना 1970 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग की एक लिजेंडरी जोड़ी थे। किशोर कुमार एक ऐसे प्रख्यात गायक थे, जिनकी आवाज़ अपने ढंग की अनूठी थी और वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा और गाने के माध्यम से विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वहीं राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे, जो अवाम के दिलों की धड़कन माने जाते थे। साथ ही वे रोमांटिक किरदारों और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। यही वजह है की आराधना, आनंद, अमरप्रेम, हाथी मेरे साथी कटी पतंग, दो रास्ते सच्चा झूठा और मेरे जीवन साथी जैसी सुपरहिट फिल्मों की एक लंबी फ़ेहरिस्त बनी। इन फिल्मों के गीत, जिनमें से कई किशोर कुमार ने गाए थे, आज भी संगीतप्रेमियों के प्रिय क्लासिक्स के रूप में पसंद किए जाते हैं। काका और किशोरदा का योगदान भारतीय फिल्म उद्योग की विरासत का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है और आनेवाली पीढ़ियों के प्रशंसकों के दिलों पर भी अमिट छाप छोड़ जायेगा। हिट सोशल सीरियो कॉमेडी जैसी बावर्ची से लेकर आंखें नम कर देती अमरप्रेम तक उन्होंने बार-बार साबित किया कि उनके पास किसी भी स्टाइल को निभाने की कूवत है। अव्वल तो उनकी फिल्में एक पीढ़ी की ख़ास-मख़्सूस पहचान थीं और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।

पब्लिक इमेज और निजी ज़िंदगी की बारीकियां

राजेश खन्ना को आमतौर पर एक रोमांटिक सुपरस्टार के रूप में देखा जाता था, जिनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन पर्सनालिटी लवर ब्वॉय होने का संकेत देती थी, लेकिन लड़कियों की चाहत लवर ब्वॉय शब्द उस जटिल वास्तविकता को सरल कर देता है, जिसे सेलिब्रिटी कल्चर, सनसनीखेज़ी मीडिया और बदलते सामाजिक मानदंडों से आकार मिला था।

सुपरस्टारडम और शख़्सियत

राजेश खन्ना (1942-2012) 1960 के दशक के अंत से 1970 के दशक तक भारत के पहले सर्वमान्य सुपरस्टार बने। उनकी ऑन-स्क्रीन इमेज, जोरदार रोमांटिक लीड, महिला प्रशंसक वर्ग के साथ ही भावुक गानों ने उनके निजी जीवन की सार्वजनिक धारणा को धुंधला कर दिया। वहीं उनके प्रशंसातीत स्टारडम ने महिलाओं के साथ उनके हर संबंध को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया।

डिंपल और काका

राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की। मगर शादी के बाद उनके बीच लंबे समय तक अलगाव बना रहा। हालांकि उन्होंने कभी औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया। यहां बता दें कि उनके अशांत वैवाहिक संबंधों के बावजूद लोग उन्हें मिलनसार मानते थे।

को-स्टार्स से काका के रिश्ते

राजेश खन्ना ने लेडीज को-स्टार्स के साथ घनिष्ठ दोस्ती निभाई और उनकी इमेज एक ऐसा व्यक्ति होने की थी, जो स्नेही, छेड़छाड़ करनेवाला और भावनात्मक रूप से गहन था। महिलाओं से आनेवाले ग्रीटिंग्स, गिफ्ट्स और तारीफ़ो ने उनके लगातार रोमांटिक संबंधों में शामिल होने के प्रभाव को बढ़ाया।

निजी जटिलताएं

मित्रों, परिवार और जीवनी लेखकों के विवरणों में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चित्रित किया गया है, जो अंतरंगता की लालसा रखता था, अकेलापन सहता था और संबंधों में गलतियां करता था। दूसरी ओर, भावनात्मक अस्थिरता, स्वामित्व की भावना और शराब का दौर उनके वैवाहिक तनाव को लगातार गहराये जा रहा था। कई करीबी सहयोगियों का दरियादिल काका को दिलफेंक मानने पर सख़्त एतराज़ बना रहा। अपने मुलाज़िमों का ख़याल रखने में उन्होंने कभी भी रत्तीभर आनाकानी नहीं की।

मीडिया का बढ़ावा

1970-90 के दशक की भारतीय टेब्लॉयड कल्चर अक़सर सेलिब्रिटी रिश्तों को सनसनीखेज बनाती थी, जिससे सत्यापित तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और अतिशयोक्ति से अलग करना मुश्किल हो जाता था।

बदलते पैमाने

तब अपमानजनक माने जानेवाले व्यवहार को अब अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि राजेश खन्ना का निजी जीवन जटिल होने से इसे एक एक शब्द में सीमित नहीं किया जा सकता।

राजेश खन्ना का जीवन करिश्माई प्रसिद्धि, रोमांटिक सार्वजनिक छवि, ज़ाहिर वैवाहिक समस्याओं और दर्ज़ किए गए संबंधों का मेलजोल था। वे मुक़म्मल तौर पर मासूम रोमांटिक या औरतों पर जान छिड़कनेवाले नहीं थे। बल्कि यह कहना बेमानी नहीं होगा कि तमाम ख़ामियों के बावजूद वे चैन-ओ-सुकून को तरसते रहे।

बॉलीवुड में 2026 होगा रोमांस का साल

टॉक्सिक, तू मेरी जिंदगी है, आवारापन 2 समेत रिलीज होंगी ये 7 फिल्में

निज संवाददाता : बॉलीवुड में 2026 रोमांस का साल होगा। आने वाला साल सिनेमा लवर्स, खासकर रोमांटिक फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए कई खूबसूरत फिल्में लेकर आ रहा है। 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स की रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी। इस लिस्ट में इमरान हाशमी से लेकर हर्षवर्धन राणे तक शामिल हैं। अनन्या पांडे, वरुण धवन से लेकर राशा थडानी तक जैसे कई स्टार किड्स भी रोमांटिक फिल्मों में दिखाई देंगे।

टॉक्सिक- A फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यश स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 12 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। A फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स में कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी।

चांद मेरा दिल: धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल भी अगले साल रिलीज के लिए तैयार है। विवेक सोनी के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे। चांद मेरा दिल 10 अप्रैल, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।

है जवानी तो इश्क होना है: है जवानी तो इश्क होना है एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण धवन लीड रोल में हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई देंगी। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी।

आवारापन 2: इमरान हाशमी की क्लासिक फिल्म आवारापन का सीक्वल आवारापन 2 अनाउंस हो चुकी है। इस रोमांटिक फिल्म को नितिन कक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि 2026 में रिलीज हो सकती है।

तू मेरी जिंदगी है: म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म तू मेरी जिंदगी है को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला इश्क फरमाते दिखाई देंगे। तू मेरी जिंदगी है 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।

सिला: एक दीवाने की दीवानियत के बाद अब हर्षवर्धन राणे फिल्म सिला में नजर आएंगे। इस रोमांटिक फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब लीड रोल निभाएंगी। सिला में करणवीर मेहरा विलेन का किरदार अदा करने वाले हैं। ये फिल्म भी 2026 में रिलीज हो सकती है।

लईकी लईका: आजाद के बाद अब राशा थडानी रोमांटिक फिल्म लईकी लइका में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ मुंज्या फेम एक्टर अभय वर्मा रोमांस करते नजर आएंगे। लईकी लईका भी अगले साल थिएटर्स में दस्तक दे सकती है।

साउथ की अभिनेत्री नंदिनी सीएम ने की खुदकुशी

निज संवाददाता : साउथ की मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदिनी सीएम नंदिनी सीएम ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि यह दुखद घटना एक डेथ सीन की शूटिंग के ठीक बाद घटी है। इस खबर से उनके फैन्स और उन्हें जानने वालों को गहरा सदमा लगा है। कन्नड़ और तमिल टेलीविजन एक्ट्रेस नंदिनी सीएम जीवा हूवागिदे, संघर्ष और गौरी जैसे धारावाहिकों के लिए जानी जाती थीं। इन टीवी शोज़ में अपने रोल के लिए फेमस एक्ट्रेस बेंगलुरु में रहती थीं। खबर है कि ये घटना बेंगलुरु के आरआर नगर में घटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी मृत्यु के समय नंदिनी एक तमिल टेलीविजन सीरियल में लीड रोल निभा रही थीं। वह फेमस धारावाहिक गौरी में एक्टिंग कर रही थीं, जिसमें उन्होंने कनक और दुर्गा का चुनौतीपूर्ण डबल रोल निभाया। सीरियल में उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के बीच पहचान दिलाई थी। इसे लोग एक दुखद संयोग ही मान रहे हैं कि तमिल सीरियल गौरी में नंदिनी की भूमिका में एक ऐसा सीन शामिल था जिसमें उनका किरदार जहर खाता है। हालांकि जांच अधिकारी उनकी भूमिका को इस घटना से जोड़कर नहीं देख रहे। फिलहाल नंदिनी सीएम की मौत की वजहों को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की ओर से घटना के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि यह दुखद घटना 28 दिसंबर, 2025 की रात 11:16 बजे से 29 दिसंबर, 2025 की सुबह 12:30 बजे के बीच की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंदिनी उस शाम अपने दोस्त पुनीत के घर गई थीं और लगभग 11:23 बजे अपने दूसरी मंजिल के कमरे में लौटी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब पुनीत ने उन्हें फोन किया तो उनसे बात नहीं हो पाई। इसके बाद वो चिंतित हो गया और उसने पीजी मैनेजर कुमार और प्रभारी किरण को सूचित किया। बताया जाता है कि दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर उन्होंने नंदिनी को उसके कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया। केंगेरी पुलिस को इसकी सूचना दी गई और उसके परिवार को सूचित किया गया, जो बल्लारी से बेंगलुरु पहुंचे।

'जेलर 2' में दिखेगी तीन सुपरस्टार की तिकड़ी

निज संवाददाता : साउथ के सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को एक ही फिल्म में देखने का सपना फैंस लंबे समय से देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से जेलर 2 में शाहरुख खान के कैमियो को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब इन अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल और तेज हो गई है। इस चर्चा की वजह बने हैं दिग्गज अभिनेता मिठुन चक्रवर्ती। एक इंटरव्यू में मिठुन चक्रवर्ती ने जेलर 2 को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। बातचीत के दौरान जब उन्होंने फिल्म के कलाकारों के नाम गिनाए तो उन्होंने कहा, मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन, शिवराजकुमार। बस यहीं से फैंस को ऐसा लगा कि शायद यह कोई इशारा नहीं, बल्कि सीधा कन्फर्मेशन है। इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर जैलर2 और एसआरके- रजनीकांत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। अगर शाहरुख खान वाकई जेलर 2 का हिस्सा बनते हैं तो यह दोनों सुपरस्टार्स का करीब 15 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करना होगा। इससे पहले शाहरुख और रजनीकांत को आखिरी बार 2011 की साइंस-फिक्शन फिल्म रा.वन में देखा गया था। उस फिल्म में रजनीकांत ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी और अपनी सुपरहिट फिल्म एंथिरन के आइकॉनिक किरदार चिट्टी रोबोट को दोहराया था। उस कैमियो को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी वह सीन याद किया जाता है। इसके बाद से दोनों दिग्गज किसी भी प्रोजेक्ट में साथ नजर नहीं आए। जेलर 2, 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर का सीक्वल होने वाला, जिसने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। रजनीकांत के दमदार अंदाज, अनिरुद्ध के म्यूजिक और पैन-इंडिया स्टारकास्ट की वजह से फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली थी। अब इसके दूसरे भाग से उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से शाहरुख खान के कैमियो को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मिठुन चक्रवर्ती के बयान ने फैंस की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है।

मतदाता सूची, एसआईआर और 2026 का विधानसभा चुनाव

आंकड़ों की रोशनी में राजनीतिक आशंका की वास्तविकता

शोभन चक्रवर्ती

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। कुछ समाचार माध्यमों और विपक्षी राजनीतिक नेताओं का दावा है कि यह प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़े राजनीतिक संकट का संकेत है। लेकिन यह आशंका कितनी वास्तविक हैइसका मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, बल्कि आंकड़ों से किया जाना चाहिए। प्रारूप सूची के अनुसार हटाए गए मतदाताओं की संख्या लगभग 58,20,898 है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 7.6 फीसद है। लेकिन जब इन आंकड़ों के पीछे के कारणों का विश्लेषण किया जाता है, तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। हटाए गए मतदाताओं में लगभग 24 लाख मृत, करीब 20 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित और 12 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित या पता नहीं चल सके। इसके अतिरिक्त डुप्लिकेट और फर्जी नाम भी शामिल हैं। स्पष्ट है कि हटाए गए नामों का बड़ा हिस्सा ऐसे मतदाताओं का है, जो वास्तव में अब सक्रिय मतदाता नहीं हैं। यहां 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आंकड़े विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उस चुनाव में राज्य में कुल मतदाता लगभग 7.34 करोड़ थे, जिनमें से करीब 5.99 करोड़ ने मतदान किया। अर्थात लगभग 1.34 करोड़ मतदाताकुल मतदाताओं का लगभग 18 फीसदने मतदान नहीं किया। यह स्वैच्छिक अनुपस्थिति की संख्या एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कहीं अधिक है। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को लगभग 47.94 फीसद मत प्राप्त हुए थे, जो संख्या के लिहाज़ से लगभग 4.8 करोड़ वोट थे। इस संदर्भ में यह मानना कठिन है कि एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं का बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस का नियमित मतदाता आधार था। वास्तविकता यह है कि हटाए गए मतदाताओं का बड़ा भाग या तो मतदान के योग्य नहीं था, या उसने पिछले चुनाव में भी मतदान नहीं किया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्तमान मतदाता सूची प्रारूप (ड्राफ्ट) है, अंतिम नहीं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार दावे और आपत्तियों के माध्यम से कई नाम दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए प्रारूप सूची के आधार पर भविष्य के चुनाव परिणामों का अनुमान लगाना राजनीतिक विश्लेषण से अधिक राजनीतिक प्रचार की रणनीति प्रतीत होता है। इस प्रकार, आंकड़े स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची को लेकर जिस भय या आशंका को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका वास्तविक आधार कमजोर है। चुनावी राजनीति में अनिश्चितताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन आंकड़े कभी भय की भाषा नहीं बोलते। और यही आंकड़े बता रहे हैं कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर 2026 के चुनाव पर मंडराने वाले संकट की कहानी, वास्तविकता की तुलना में काफी हद तक अतिरंजित है।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय** : 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय** : 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता**, मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)